



- संसद 54 दिन से बिना बैठक के, 37 साल का रिकॉर्ड टूटा, विशेष सत्र की अटकलें



**पश्चिम बंगाल का
नाम बदलकर होगा
पश्चिम बंग!**

- शमिक भट्टाचार्य बोले-बिल लेकर आ रही सरकार



इस्तेमाल अब नहीं किया जाएगा। भट्टाचार्य ने सीमावार को कहा था, बिस्तुल। पश्चिम बंगाल भवन... पश्चिम बंगाल का पश्चिम... अब आपको लंबे समय तक पश्चिम बंग, बांग्ला या बंगा जैसे नाम सुनने को नहीं मिलेंगे। पश्चिम बंग नाम आ रहा है। प्रस्तावित कानूनी कदम के बारे में बताते हुए बीजेपी के राज्य प्रमुख ने कहा कि इन्हें बिल का मकसद राज्य के आधिकारिक नाम को उसकी ऐतिहासिक पहचान से जोड़ना है। उन्होंने कहा, बहुत जल्द पहले ही सत्र में हमारी सरकार एक बिल पेश करने जा रही है ताकि इस राज्य का नाम राज्य के इतिहास से गहराई से जुड़ा रहे और यही इसकी पहचान बनी रहे। इसीलिए राज्य का नाम पश्चिम बंग रखा जा रहा है।

महंगाई बढ़ी, अब कर्ज लेना और चुकाना भी होगा महंगा

नई दिल्ली (एजेंसी)। महंगाई बढ़ गई है, यह और बढ़ने वाली है, यह तय है। साथ में बैंकों से कर्ज लेना भी महंगा होने वाला है। ये बातें रिजर्व बैंक, यानी आरबीआई को हैं। इसके चलते आरबीआई को फरवरी 2023, यानी करीब 4 साल बाद रेपो रेट पब्लिश पड़ा है। रेपो रेट 5.25 से बढ़कर 5.50 फीसदी कर दिया है। अब ये क्यों किया, इस समझने के लिए सबसे पहले रेपो रेट समझना जरूरी है। रेपो रेट वो ब्याज दर है जिस पर बैंक आरबीआई से कर्ज लेता है। फॉर्मूला ये है कि रिजर्व बैंक महंगा कर्ज बैंकों को देगा तो बैंक लोगों को और महंगा कर्ज देंगे। इससे लोग कम कर्ज लेते और खर्च कम करेगे। खर्च होगा मांग कम होगी, मांग कम होने से महंगाई काबू में रहेगी।

फिलहाल ब्याज दरें घटने का रास्ता बंद

आरबीआई ने अपना रुख बदलकर 'कैलिब्रेटेड टाइमिंग' कर दिया है। यानी, फिक्कल ब्याज दरों में कटौती का रास्ता पूरी तरह से बंद हो चुका है। आने वाली बैठकों में रिजर्व बैंक या तो दरों को जैसा है वैसा ही रखेगा, या फिर जरूरत पड़ने पर इन्हें आगे बढ़ा सकता है। रिलेगियर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा का कहना है कि 0.25 फीसदी की हद बढाती तो उम्मीद के मुताबिक ही थी, लेकिन असली बात नीति में हुआ बदलाव है। इससे साफ जाहिर होता है कि रिजर्व बैंक के लिए अब सबसे पहला काम महंगाई पर काबू पाना है।

जेल से ही बीमार दादी को वीडियो कॉल करेगा अमृतपाल

अमृतसर की कोर्ट ने दी 10 मिनट बात करने की इजाजत

अमृतसर (एजेसी)। जिला
अदालत ने खड्डूर साहिब के सांसद और
वारिस पंजाब दे के नेता अमृतपाल सिंह
को अपनी बीमार दादी से 10 मिनट की
वीडियो कॉल पर बात करने की इजाजत
दी है। वर्तमान में अमृतपाल सिंह अस्म



की डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल में बंद हैं। अमृतसर के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बरिंदर सिंह ने अमृतपाल के वकीलों की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। अमृतपाल सिंह की ओर से पेशर उनके वकीलों ने अदालत में याचिका दायर की थी और उनकी दादी की बीमारी को देखते हुए अदालत से वीडियो कॉल के जरिए उनसे बातचीत करने की अनुमति मांगी थी।

भारत के विकसित होने तक न थकूंगा न रुकूंगा: मोदी

- मोदी 50 मिनट में 19 बार
बोले-वी विल डू इट ● बतौर पीएम-सीएम
25 साल पूरे, रिकॉर्ड बनाया

नई दिल्ली/वडनगर (एजेंसी)। 'वी विल डू इट...' हम करके दिखाएंगे। पीएम मोदी ने बुधवार को अपने सार्वजनिक जीवन के 25 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में इस नारे का 19 बार जिक्र किया। उन्होंने एक घंटे की स्पीच में कहा, जब तक भारत विकसित नहीं होता, तब तक न थकूंगा, न रुकूंगा।' उन्होंने कहा, 'मैं महत्वाकांक्षी नहीं, मिशन के लिए जीता हूं। जिसने मुझे गिराया, उसी ने खड़ा होना सिखाया। जिसने मेरा विरोध किया, उसने लोकतंत्र की शक्ति समझाई।' उन्होंने कहा कि 25 साल पीछे मुड़कर देखने पर उपलब्धियों से ज्यादा कृतज्ञता का भाव आता है। हर घटना ने कुछ सिखाया और नम्र होना सिखाया। ईश्वर से ये मांगें की जा सकती हैं कि इच्छा कभी कम न हो। मोदी ने कहा, हमने इस राष्ट्र में जन्म लिया है, ये एहसास ही अमृत है। इसके सामने सत्ता सुख कुछ नहीं है। पद-प्रतिष्ठा तो कहीं भी मिल सकती है, लेकिन भारत जैसी पुण्यभूमि नहीं मिलेगी।



25 साल में देश कहां पहुंचा, ये अहम

भारत, जिसने
अधिकार के युग में भी
मानवता को ज्ञान
का देया, मृत्यो का
दकाश इसका, उसका
मेवा का मौका
अमूल्य है। 125 सालों
का अंकलन इससे
ही होगा कि मैं कहां
हुंवा, बल्कि इससे
गंगा कि मेरा देश
कहां पहुंचा। पीएम
मोदी ने कहा देश का
नफा देना बहुत जरूरी
। हमारी सरकार ने
कमिश्नर भारत के
लेप 2047 का लक्ष्य
का है और हम इसी
मेशन पर लगातार
काम कर रहे हैं। यह
हमारी सरकार का
गौर हमारा भी
सम्पना है।

सांसद परिमल नाथवानी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पूज्य माताजी के निधन पर जताया शोक

दैनिक अलग पहचान, अन्नपूर्णा गुप्ता, मुख्य संपादक, नई दिल्ली

झारखंड से 'य' रासभा सांसद परमिल नाथवानी ने कहा दिशोम गुरु जो महान आदिवासी नेता स्वर्गीय श्री शिबू सोरेन जी की धर्मपत्नी एवं झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी की 'पू'य माताजी श्रीमती रूपी सोरेन जी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है।



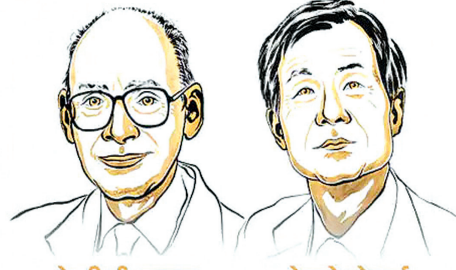
**दैनिक अलग पहचान,
डेस्क संवाददाता, संची /**

राजी।एसआईआर में अभी भी झारखंड के छुट्टी पत्र भारतीय नागरिक 7,8 एवं 9 अक्टूबर को आयोजित डिजिटाइजेशन कैम्प अथवा 10 अक्टूबर को आयोजित मेगा हेल्पडेस्क में शामिल होकर अपना नाम मतदाता सूची में अवश्य नुदवाएं - पदाधिकारी के. रवि कुमार, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, झारखंड।

2026 का केमिस्ट्री नोबेल फ्रांस-जापान के वैज्ञानिकों को

- अणुओं के मिरर इमेज की 100 साल पुरानी गुथी सुलझाई, दवाएं बनाने में मदद मिली

स्टॉकहोम (एजेंसी)। 2026 का केमिस्ट्री नोबेल पुरस्कार फ्रांस के वैज्ञानिक हेनरी बी. कागन और जापान के केन्सो सोआई को दिया गया है। दोनों वैज्ञानिकों ने रसायन विज्ञान की करीब 100 साल पुरानी गुथी सुलझाई है। हेनरी बी. कागन और केन्सो सोआई ने यह समझना में बड़ी मदद की कि मिटर इमेज जैसे दिखने वाले दो अणुओं में से सिर्फ एक को कैसे बनाया जा सकता है। यह खोज खास तौर पर दवाएं बनाने में काम आ रही



है। नोबेल पुरस्कार के

केन्सो सोआई

हे। नोबेल पुरस्कार के विजेताओं को दिसंबर में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में सम्मानित किया जाएगा। उन्हें मेडल, डिप्लोमा और पुरस्कार राशि दी जाएगी। 2026 में नोबेल पुरस्कार की राशि करीब 11.5 करोड़ रुपए है।

बनाया जाए- हमारे शरीर में अमीनो एसिड से प्रोटीन बनता है। अमीनो एसिड के दो रूप हो सकते हैं, जो एक-दूसरे की मिरर इमेज होते हैं। लेकिन शरीर प्रोटीन बनाने के लिए इनमें से सिर्फ एक रूप का इस्तेमाल करता है। वैज्ञानिकों का सवाल था कि जब दोनों रूप बन सकते हैं, तो शरीर सिर्फ एक को ही क्यों चुनता है। 1986 में हेनरी बी. कागन ने इसका एक अद्भुत रास्ता बताया। उन्होंने एक ऐतिहासिक तरीका खोजा।

बनाया जाए- हमारे शरीर में अमीनो एसिड से प्रोटीन बनता है। अमीनो एसिड के दो रूप हो सकते हैं, जो एक-दूसरे की मिरर इमेज होते हैं। लेकिन शरीर प्रोटीन बनाने के लिए इनमें से सिर्फ एक रूप का इस्तेमाल करता है। वैज्ञानिकों का सवाल था कि जब दोनों रूप बन सकते हैं, तो शरीर सिर्फ एक को ही क्यों चुनता है। 1986 में हेनरी बी. कागन ने इसका एक अद्भुत रास्ता बताया। उन्होंने एक ऐतिहासिक तरीका खोजा।

**सोआईनेऐसाअणुबनाया
जोअपनेजैसेअणुबनाताथा**

इसके बाद केन्सो सोआई ने कागन के काम को आगे बढ़ाया। उन्होंने १-पाइरिडिडिल एक्केनॉल नाम के एक रासायनिक पदार्थ पर प्रयोग किए। उन्होंने ऐसी प्रक्रिया बनाई, जिसमें एक तरह का अणु बनने के बाद वह अपने जैसे दूसरे अणु बनने में मदद करता था। इसे ऐसे समझिए - शुरुआत में वही किसी एक तरह के अणु थोड़े ज्यादा बन गए, तो अगले अणु आगे और अपने जैसे अणु बनाने में मदद करने लगे। फिर नए बने अणु भी वही काम करने लगे। इस तरह एक तरह के अणुओं की संख्या लगातार बढ़ती गई। १९९५ के प्रयोग में शुरुआत में एक तरह के अणु की मात्रा सिर्फ २ फीसदी ज्यादा थी। लेकिन प्रक्रिया चलने के बाद यह बढ़कर ८७ फीसदी तक पहुंच गई। यानी शुरुआत का छोटा - सा फर्क बहुत बड़ा हो गया।

धनबाद: जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया



दैनिक अलग पहचान, डेस्क संवाददाता, रांची /

धनबाद। उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी आदित्य रंजन ने बैंक मोड़ स्थित खालसा स्कूल के मतदान केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कार्य की प्रगति देखी और बूथ संख्या 208 से 339 की बीएलओ को दस्तावेज अपलोडिंग में त्रुटि न करने के निर्देश दिए। उपायुक्त ने कहा कि मतदाता सूची का कार्य संवेदनशील है, इसमें लापरवाही न बरती जाए और शत-प्रतिशत त्रुटि रहित सूची तैयार की जाए।

धनबाद में जन सुविधा केंद्र और हेल्प डेस्क का उद्घाटन



दैनिक अलग पहचान, डेस्क संवाददाता, रांची /

धनबाद। समाहरणालय में जन सुविधा-सह-प्रशिक्षण केंद्र और हेल्प डेस्क का उद्घाटन सांसद दुल्लू महतो, चंद्र प्रकाश चौधरी और उपायुक्त आदित्य रंजन ने किया। DMFT मद से सरकारी स्कूलों के लिए मध्यह्न भोजन के बर्तन और स्वास्थ्य सहायता दीर्घियों के लिए मेडिकल किट का वितरण किया गया। अतिथियों ने कहा कि इससे प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ेगी और लोगों को अपनी समस्याओं के लिए भटकना नहीं पड़ेगा।

इंजीनियरिंग के मूल सिद्धांतों की समझ जरूरी- डॉ. उदय सिंह



दैनिक अलग पहचान, डेस्क संवाददाता, रांची /

रांची। सरला बिरला विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग के मूल सिद्धांतों और उनके व्यावहारिक उपयोग पर एक्सपर्ट टॉक का आयोजन किया गया। आयोजन सरला बिरला विश्वविद्यालय और यूनिवर्सिटी ऑफ़ मिनेसोटा के बीच हुए शैक्षणिक कारगर के तहत किया गया था। कार्यक्रम में यूनिवर्सिटी ऑफ़ मिनेसोटा के बायो-प्रोडक्ट्स एंड बायोसिस्टम्स इंजीनियरिंग विभाग के प्राध्यापक डॉ. उदय बी. सिंह ने विद्यार्थियों और शिक्षकों को संबोधित किया। इस अवसर पर डॉ. सिंह ने कहा कि आज एआई तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसका प्रभाव लगभग हर क्षेत्र में नजर आता है। ऐसे समय में केवल नई तकनीक के पीछे चलने के बजाय इंजीनियरिंग के मूल सिद्धांतों को समझना जरूरी है। मजबूत बुनियादी ज्ञान, तार्किक सोच और समस्या का व्यावहारिक समाधान खोजने की क्षमता ही इंजीनियरों को बेहतर बनाने में मदद करती है। उन्होंने विद्यार्थियों को सलाह दी कि वे नई तकनीकों को सीखने के साथ-साथ अपने मूल विषयों की समझ भी मजबूत करें। उन्होंने कहा कि इंजीनियरिंग का उद्देश्य केवल तकनीक का इस्तेमाल करना नहीं, बल्कि समाज और वास्तविक जीवन की समस्याओं का उपयोगी और टिकाऊ समाधान तैयार करना है। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के महानिदेशक प्रो. गोपाल पाठक, कुलपति प्रो. सी. जगनाथन, कुलसचिव प्रो. एस. बी. डॉइन सहित डीन, एसोसिएट डीन और विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष उपस्थित रहे। सरला बिरला विश्वविद्यालय के प्रतिकुलाधिपति बिजय कुमार दलान एवं राज्यसभा सांसद सह निदेशक प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डॉ. प्रदीप कुमार वर्मा ने एक्सपर्ट टॉक के आयोजन के निमित्त आयोजक मंडली को शुभकामना सदेश प्रेषित किया है।

7, 8 एवं 9 अक्टूबर को राज्यभर में चलाए जा रहे विशेष डिजिटाइजेशन कैंप

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने चतरा एवं सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न केंद्रों का किया निरीक्षण



दैनिक अलग पहचान, डेस्क संवाददाता, रांची /

रांची। एसआईआर-2026 में छूटे हुए पात्र भारतीय नागरिकों को मतदाता सूची में शामिल करने एवं निर्वाचन संबंधी कार्यों को गति देने के उद्देश्य से राज्यभर में 7, 8 एवं 9 अक्टूबर को विशेष डिजिटाइजेशन कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कार्यक्रम के तहत मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, झारखण्ड श्री के. रवि कुमार ने चतरा जिले के चतरा एवं सिमरिया विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के विभिन्न मतदान केंद्रों पर आयोजित विशेष डिजिटाइजेशन केंद्रों का निरीक्षण किया तथा वहां किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए कैंप में आने वाले नागरिकों को हरसंभव सहयता उपलब्ध कराने को कहा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि विशेष डिजिटाइजेशन कैंप का स्थानीय स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए, ताकि अधिक से अधिक पात्र भारतीय नागरिक इसकी जानकारी प्राप्त कर निर्धारित तिथियों में अपने मतदान केंद्र पर पहुंचकर आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर सकें। भारत निर्वाचन

आयोग ने भी स्थानीय स्तर पर जागरूकता एवं मोबिलाइजेशन गतिविधियों के माध्यम से प्रत्येक पात्र नागरिक को मतदाता सूची में नामांकन के अवसर की जानकारी देने पर जोर दिया है। पदाधिकारी के. रवि कुमार ने कहा कि जो पात्र भारतीय नागरिक किसी कारणवश एसआईआर के दौरान अभी तक मतदाता सूची में अपना नाम नहीं जुड़वा पाए हैं, वे 7, 8 एवं 9 अक्टूबर को अपने मतदान केंद्र पर आयोजित विशेष डिजिटाइजेशन कैंप में पहुंचकर फॉर्म-6 के माध्यम से अपना नाम मतदाता सूची में अवश्य जुड़वाएं। उन्होंने जिला

निर्वाचन पदाधिकारियों, ईआरओ, ईआईआरओ एवं बीएलओ को ऐसे नागरिकों की पहचान कर उन्हें नामांकन की प्रक्रिया में आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इन विशेष कैंपों में एसआईआर के दौरान नोटिस की सुनवाई के क्रम में मतदाताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों के डिजिटाइजेशन का कार्य भी किया जा रहा है। इसके साथ ही?? बीएलओ को प्राप्त फॉर्म-6, फॉर्म-7 एवं फॉर्म-8 सहित अन्य संबंधित आवेदनों के डिजिटाइजेशन में भी तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्य निर्वाचन

पदाधिकारी ने कहा कि मतदाता सूची में नामांकन एक सतत प्रक्रिया है। कोई भी पात्र भारतीय नागरिक, जो अभी तक मतदाता सूची में शामिल नहीं हो पाया है, नामांकन के लिए आवेदन कर सकता है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार विशेष अभियान का उद्देश्य ऐसे छूटे हुए एवं पहली बार/युवा मतदाताओं के नामांकन की प्रक्रिया को सुगम बनाना है। उन्होंने कहा कि कोई भी पात्र भारतीय नागरिक मतदाता सूची से वंचित न रहे, इसके लिए सभी पदाधिकारी समन्वित रूप से कार्य करें। विशेष रूप से जनजातीय समूहों, पिछड़े वर्गों, दिव्यांगजनों, वृद्ध मतदाताओं, थर्ड जेंडर, सेक्स वर्कर्स, आश्रय गृहों, श्रमिक बस्तियों तथा अन्य वंचित वर्गों के पात्र नागरिकों तक पहुंच बनाकर उन्हें मतदाता सूची में नामांकन की प्रक्रिया के संबंध में आवश्यक सहयता उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। भारत निर्वाचन आयोग ने भी कमजोर एवं वलनरेबल समूहों तक पहुंचने के लिए विशेष कैंप आयोजित करने पर जोर दिया है। पदाधिकारी के. रवि कुमार ने सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि विशेष डिजिटाइजेशन कैंपों का क्षेत्र भ्रमण कर नियमित निरीक्षण करें और कैंप में प्राप्त आवेदनों एवं

दस्तावेजों के डिजिटाइजेशन की प्रगति की समीक्षा करें। उन्होंने कहा कि स्थानीय स्तर पर सोशल मीडिया, स्थानीय जनप्रतिनिधियों, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, शैक्षणिक संस्थानों तथा अन्य माध्यमों से व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाए। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के निर्देशानुसार सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों ने भी अपने अपने क्षेत्रों में आयोजित विशेष कैंपों का दौरा किया। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि 10 अक्टूबर को राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर मेगा हेल्पडेस्क का आयोजन किया जाए। मेगा हेल्पडेस्क के माध्यम से नागरिकों को मतदाता सूची में नाम जोड़ने, दावा-आपत्ति, नोटिस की सुनवाई तथा निर्वाचन संबंधी अन्य प्रक्रियाओं के संबंध में आवश्यक जानकारी एवं सहयता उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने राज्य के सभी पात्र नागरिकों से अपील की है कि यदि उनका नाम अभी तक मतदाता सूची में दर्ज नहीं हुआ है, तो 7, 8 एवं 9 अक्टूबर को अपने मतदान केंद्र पर आयोजित विशेष डिजिटाइजेशन कैंप में अवश्य पहुंचें और फॉर्म-6 के माध्यम से अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने की प्रक्रिया पूरी करें।

दुर्गा पूजा से पहले राज्य की महिलाओं को झारखंड सरकार का उपहार

मईयां सम्मान योजना के तहत रांची जिले की 03 लाख 93 हजार 994 लाभुकों के खाते में सितंबर माह की सम्मान राशि का भुगतान



दैनिक अलग पहचान, डेस्क संवाददाता, रांची /

रांची। दुर्गा पूजा से पहले राज्य की महिलाओं को झारखंड सरकार का उपहार मिला है। सरकार की महत्वाकांक्षी झारखंड मुख्यमंत्री मईयां सम्मान योजना के अंतर्गत रांची जिले की 03 लाख 93 हजार 994 लाभुकों के बैंक खातों में सितंबर 2026 की सम्मान राशि का भुगतान कर दिया गया है। प्रत्येक लाभुक को 72,500 की सम्मान राशि आधार बेरुख डायरेक्ट बेंचिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की गई है। योजना के तहत रांची जिले में लाभुकों के खातों में कुल 798 करोड़ 49 लाख 85 हजार की सम्मान राशि

हस्तांतरित की गई है। दुर्गा पूजा से पहले राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के खातों में सम्मान राशि का भुगतान किया जाना महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त, रांची मंजूनाथ भजन्नी ने कहा कि झारखंड मुख्यमंत्री मईयां सम्मान योजना के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है। सितंबर माह की सम्मान राशि का समय पर भुगतान यह सुनिश्चित करता है कि योजना का लाभ पात्र लाभुकों तक सीधे और सुगम तरीके से पहुंचे। उन्होंने कहा कि दुर्गा पूजा के अवसर से पहले सम्मान राशि का भुगतान महिलाओं एवं उनके परिवारों के लिए आर्थिक संबल प्रदान करने वाला महत्वपूर्ण कदम है।

प्रखंड एवं शहरी क्षेत्रवार लाभुकों को भुगतान की स्थिति इस प्रकार है:-

1. अनगड़ा - 16,681
2. अरगोड़ा शहरी क्षेत्र - 13,347
3. बड़गाई शहरी क्षेत्र - 10042
4. बेड़ो - 20,555
5. बुड़ू - 8,566
6. बुड़ुनगर पंचायत - 3,558
7. बुढूम - 17,760
8. चाही - 19,336
9. हेहल शहरी क्षेत्र - 16,285
10. इटकी - 10,136
11. कांके - 31,483
12. कांके शहरी क्षेत्र - 1,281
13. खलारी - 9,590
14. लापुंग - 11,819
15. मांडर - 22,936
16. नगड़ी - 18,281
17. नगड़ी शहरी क्षेत्र - 8,210
18. नामकुम - 17,942
19. नामकुम शहरी क्षेत्र - 9,493
20. ओरमांझी - 18,847
21. रहै - 9,527
22. रातू - 20,329
23. सिल्ली - 21,269
24. सोनाहातू - 13,084
25. तमाड़ - 18,744
26. टाउन अर्बन - 25,893

माता-पिता की असामयिक मृत्यु से बेस हारा हुए बच्चों तक पहुंचा जिला प्रशासन



दैनिक अलग पहचान, डेस्क संवाददाता, रांची /

रांची। रांची जिले के तमाड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत कुंदला पंचायत के लेकया गाँव निवासी योगेन्द्र मुंड़ा एवं उनकी पत्नी सावित्री देवी के असामयिक निधन के बाद उनके बच्चों के समक्ष उत्पन्न कठिन परिस्थितियों पर जिला प्रशासन ने संवेदनशीलता के साथ संज्ञान लिया है। विभिन्न माध्यमों से प्राप्त सूचना पर जिला दंडाधिकारी-सह-उपायुक्त, रांची मंजूनाथ भजन्नी के निदेशानुसार दोनों बच्चों के परिवार को आवश्यक राहत उपलब्ध कराई गई। परिवार को कंबल एवं राशन सामग्री प्रदान की गई, ताकि तत्काल आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। बच्चों की शिक्षा एवं बेहतर भविष्य को ध्यान में रखते हुए दोनों बच्चों का प्रखण्ड के ही गुरुकुल विद्यालय में दाखिला कराया गया है।

विद्यालय में बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, ड्रेस एवं छात्रावास की सुविधा उपलब्ध होगी। इससे बच्चों की पढ़ाई निर्बाध रूप से जारी रखने के साथ-साथ उनके सुरक्षित एवं समुचित देखभाल की भी व्यवस्था सुनिश्चित हुई है। इसके अतिरिक्त, बच्चों को बाल संरक्षण विभाग की Sponsorship योजना से जोड़ने की प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी गई है, ताकि उन्हें आगे भी आवश्यक संरक्षण, सहयोग एवं सहयता उपलब्ध कराई जा सके। मामले में अनुमंडल पदाधिकारी, बुड़ू मनोहर लाल मरांडी एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, तमाड़ द्वारा आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की गई। जिला प्रशासन का प्रयास है कि किसी भी परिस्थिति में माता-पिता को खो चुके बच्चों को अकेलेपन और अभाव का सामना न करना पड़े तथा उन्हें शिक्षा, संरक्षण, पोषण एवं सुरक्षित भविष्य के लिए आवश्यक सहयोग समय पर उपलब्ध कराया जा सके।

आपसी चंदे से चलने वाली हरिओम सेवा संस्था के समाजसेवी को मिला सम्मान

दैनिक अलग पहचान, धनबाद ब्यूरो चीफ, शीतल दत्ता , रांची/

धनबाद। बलियापुर (धनबाद): समाज में सकारात्मक बदलाव लाने और जनसरोकार की पत्रकारिता को मजबूत करने के उद्देश्य से कावेरी रेस्टोरेंट में ‘दबंग हिंद’ न्यूज़पेपर के नए कार्यालय का भव्य उद्घाटन सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस गरिमामयी समारोह के शुभ उपलक्ष्य पर क्षेत्र की सुप्रसिद्ध सामाजिक संस्था ‘हरिओम सेवा संस्था’ के सदस्यों को उनके उत्कृष्ट सामाजिक कार्यों के लिए सम्मानित किया गया।

आपको बता दें कि ‘हरिओम सेवा संस्था’ पूरी तरह से आपसी चंदे से संचालित होती है। बिना किसी सरकारी सहयता के, संस्था के सदस्य लगातार समाज के वंचित, असहाय और जरूरतमंद वर्गों की सेवा में समर्पित रहते हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, आपदा प्रबंधन और पर्यावरण रक्षा (पौधारोपण) जैसे क्षेत्रों में संस्था द्वारा किए गए निस्वार्थ



प्रयासों को देखते हुए उन्हें यह सम्मान प्रदान किया गया।

समारोह में मुख्य रूप से उपस्थित पूर्वांचल के वरिष्ठ संपादक गणेश मिश्रा के हाथों संस्था के संस्थापक सदस्य विनोद सिंह, डॉ. स्वरूप चौधरी (अध्यक्ष) एवं मीडिया

प्रभारी शीतल दत्ता को उनकी निस्वार्थ सेवा और शानदार योगदान के लिए सम्मानित किया गया। समारोह के दौरान वरिष्ठ संपादक गणेश मिश्रा और अन्य मुख्य अतिथियों ने हरिओम सेवा संस्था के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि बिना किसी स्वार्थ के, केवल आपसी सहयोग से इतनी बड़ी संस्था चलाना और समाज की सेवा करना अत्यंत प्रेरणादायक है। मीडिया और सामाजिक संस्थाएं जब एक साथ मिलकर काम करती हैं, तो समाज के अंतिम व्यक्ति तक मदद पहुंचाना आसान हो जाता है। सम्मान प्राप्त करने के बाद हरिओम सेवा संस्था के पदाधिकारियों ने ‘दबंग हिंद’ न्यूज़पेपर की प्रभारी राजेंद्र वर्मा जी एवं पूरी टीम को नए कार्यालय की बधाई और शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा, ‘यह सम्मान हमारी पूरी टीम की मेहनत है जो हम पर भरोसा करते हैं। ‘दबंग हिंद’ ने हमें जो सम्मान दिया है, उससे हमारी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। हम भविष्य में और अधिक ऊर्जा के साथ समाज सेवा और पर्यावरण

संरक्षण के कार्यों को जारी रखेंगे। ‘ संस्था को मिले इस गौरवपूर्ण सम्मान पर संस्था के अन्य वरिष्ठ सदस्यों, सलाहकारों और सक्रिय साथियों ने हर्ष व्यक्त करते हुए पूरी टीम की सराहना की और बधाई दी। बधाई देने वालों में मुख्य रूप से अजय जी, वरिष्ठ संपादक सदस्य प्रेमांशु पाल, प्रभास पाल, सूर्य गोपाल भट्टाचार्य, सलाहकार डॉ. राजेश सिंह, एवं वरिष्ठ पत्रकार प्रसून दास गुप्ता, व सक्रिय सदस्य हार्द बाउरी, शंकर दास, दिलीप चौहान, प्रमुख प्रतिनिधि विजय रावण, ई चक्रवर्ती, अमित बनर्जी, कृष्णा दा, रंजीत महतो, आमोद बाबरी, मुकेश महतो, निरंजन प्रमाणिक, विजय दत्ता, साजिद हुसैन, अनिल महतो, रंजीत चौहान , राजा राम रवानी ,बनवारी कुभरका, दिनेश महतो, चंदन ,सहित संस्था के अन्य कई सदस्य शामिल रहे। इस अवसर पर क्षेत्र के कई गणमान्य नागरिक, वरिष्ठ पत्रकार, समाजसेवी और दोनों संस्थाओं के सक्रिय सदस्य मुख्य रूप से उपस्थित थे।

दुर्गा पूजा को लेकर प्रशासन अलर्ट,

पूजा समितियों के साथ हुई बैठक, सुरक्षा व्यवस्था पर बनी रणनीति

देवघर, एजेंसी। दुर्गा पूजा को लेकर देवघर जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। पूजा के दौरान विधि-व्यवस्था, पंडालों में सुरक्षा, साफ-सफाई और श्रद्धालुओं की सुविधा समेत विभिन्न व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन ने निगरानी तेज कर दी है। इसी क्रम में पुलिस टीम की ओर से पूजा समिति और शांति समिति के सदस्यों के साथ अहम बैठक आयोजित की गई।

बैठक में देवघर की विभिन्न पूजा समितियों के पदाधिकारी शामिल हुए। इस दौरान पूजा में आने वाली संभावित समस्याओं और उनके समाधान को लेकर प्रशासन तथा पूजा समितियों के बीच चर्चा हुई।

बैठक में शिवलोक परिसर सार्वजनिक पूजा समिति से जुड़े सदस्यों ने कहा कि दुर्गा पूजा के दौरान सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। दर

रात तक बड़ी संख्या में लोग पंडालों में पहुंचते हैं। ऐसे में नशे की हालत में घूमने वाले लोगों पर प्रशासन को सख्ती बरतने की जरूरत है, ताकि पूजा का माहौल शांतिपूर्ण बना रहे।

पूजा समितियों के साथ हुई बैठक को लेकर देवघर के एसडीपीओ कुलदीप कुमार ने बताया कि दुर्गा पूजा के दौरान जिला प्रशासन और पूजा समितियों के बीच बेहतर समन्वय बनाए रखने के उद्देश्य से लगातार बैठकों की जा रही हैं। देवघर के सभी थाना क्षेत्रों में स्थानीय लोगों और पूजा समितियों के साथ बैठक कर जरूरी दिशा-निर्देश दिए जा रहे हैं।

उन्होंने बताया कि बैठक में खास तौर पर साफ-सफाई और महिला सुरक्षा पर जोर दिया जा रहा है। पंडालों में श्रद्धालुओं के प्रवेश और निकास के लिए अलग-अलग दो रास्ते रखने को कहा गया है, ताकि भीड़ के दौरान किसी



तह की परेशानी न हो। इस निर्देश पर पूजा समितियों ने भी प्रशासन को भरोसा दिलाया है। इसके साथ ही भीड़ और व्यवस्था को संभालने के लिए पर्याप्त संख्या में वॉलंटियर्स की तैनाती की जाएगी।

प्रशासन की ओर से पूजा समितियों को

निर्देश दिया गया है कि पंडालों में तैनात किए जाने वाले सभी वॉलंटियर्स की सूची प्रशासन को उपलब्ध कराई जाए।

इससे जरूरत पड़ने पर प्रशासन स्थानीय वॉलंटियर्स के साथ समन्वय स्थापित कर किसी भी विपरीत परिस्थिति से निपट सकेगा।

रांची में दुर्गा पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक

दैनिक अलग पहचान, डेस्क संवाददाता, रांची /

रांची। समाहरणालय में उपायुक्त मंजूनाथ भजन्नी और स्क्राफेस रंजन की अध्यक्षता में केंद्रीय शांति समिति की बैठक हुई। उपायुक्त ने कहा कि इस बार दुर्गा पूजा में महिलाओं की सहभागिता बढ़ी है, जो मुख्यमंत्री के निर्देश पर सुनिश्चित की गई है। स्क्रू ने कहा कि पूजा के दौरान पुलिस पूरी तरह मुस्तैद रहेगी। सोशल मीडिया पर निगरानी, चेन छिनतई पर रोक और ट्रैफिक व भीड़ प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। प्रशासन ने पंडाल संचालकों से सुरक्षा निर्देशों का पालन करने और आम लोगों से अफवाहों से बचने और शांति बनाए रखने की अपील की है।



संक्षिप्त समाचार

आत्मरक्षा के गुर सिखाने के लिए धनबाद की बेटियां को मिलेगा प्रशिक्षण



धनबाद, एजेंसी। राज्य में बेटियों को आत्मनिर्भर और सुरक्षित बनाने की दिशा में एक महत्वापूर्ण पहल शुरू की गई है। जिले के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली क़रीब 12 हजार छात्राओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए उपायुक्त आदित्य रंजन की मौजूदगी में जिला शिक्षा विभाग और संबंधित खेल संघों के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। बालिकाओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाने के लिए धनबाद जिले में रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। कार्यक्रम के तहत जिले के 100 सरकारी विद्यालयों के साथ 16 पीएम गी विद्यालयों में भी बालिकाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इनमें 50 मध्य विद्यालयों की छात्राओं को ताड़वांडी और 50 उच्च विद्यालयों की छात्राओं को कराटे का प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम के संचालन को लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी अभिषेक झा ने संबंधित ताड़वांडी और कराटे संघ के सदस्यों के साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। 3 महीने तक चलने वाले इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में हर महीने 12 प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जाएंगे। हर सत्र दो घंटे का होगा। प्रशिक्षण पूरा करने वाली छात्राओं को संबंधित संस्था की ओर से अनुभव प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। इस पहल से क़रीब 12 हजार छात्राओं को आत्मरक्षा के साथ-साथ आत्मविश्वास बढ़ाने का अवसर मिलेगा। उपायुक्त आदित्य रंजन ने अधिकारियों और प्रशिक्षण संस्थाओं को कार्यक्रम का संचालन निर्धारित समय के भीतर और प्रभावी तरीके से सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है, ताकि अधिक से अधिक छात्राएं इस पहल से लाभान्वित हो सकें। इस दौरान कार्यक्रम के दौरान प्रमाण प्रमाणी डी। गीतू सिन्हा, धनबाद जिला ओलंपिक संघ के प्रतिनिधि पवन कुमार बरनवाल, कराटे संघ की सचिव पेगोला देवी और ताड़वांडी संघ के सचिव कमलेश पांडे मौजूद रहे।

ओबीसी आरक्षण की मांग को लेकर आज पांच जिलों में बंद, गुमला में विरोध प्रदर्शन



गुमला/सिमडेगा, एजेंसी। ओबीसी समाज द्वारा आरक्षण और जनगणना कॉलम की मांग को लेकर झारखंड के पांच जिलों सिमडेगा, गुमला, खूंटी, रांची एवं लोहरदगा में बंद बुलाया गया है, जिसका गुमला में व्यापक असर देखने को मिल रहा है। सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए और चक्का जाम कर दिया, जिससे वाहनों का आवागमन पूरी तरह ठप है। केंद्रीय पिछड़ा वर्ग संघर्ष समिति ने ओबीसी के अधिकारों और विभिन्न मांगों को लेकर सोमवार को जिला मुख्यालय में मशाल जुलूस एवं पुतला दहन कार्यक्रम आयोजित किया था। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मशाल लेकर सड़क पर उतरे और ओबीसी समाज के अधिकारों के समर्थन में आवाज बुलंद की। समिति का कहना है कि राज्य के 7 जिलों में रैपेक्टर के तहत आरक्षण शूट्य करने और जनगणना में पिछड़ा वर्ग का कॉलम नहीं रखने के विरोध में बंद बुलाया गया है। झारखंड में पिछड़ा वर्ग को नौकरी में आरक्षण, राजनीति में भागीदारी तथा पेसा-कानून में अधिकार सहित विभिन्न मुद्दों पर अपेक्षित अधिकार नहीं मिल रहे हैं। समिति ने वर्तमान जनगणना में ओबीसी का कॉलम शामिल करने तथा ओबीसी को उसके सवैधाधिक अधिकार दिलाने की मांग उठाई है। नैनर के माध्यम से समिति ने बताया कि इन मांगों को लेकर पांच जिलों सिमडेगा, गुमला, खूंटी, रांची एवं लोहरदगा में चरणबद्ध आंदोलन किया जा रहा है। आंदोलन के तहत 5 अक्टूबर 2026 को जिला मुख्यालय में मशाल जुलूस एवं पुतला दहन किया गया था। वहीं 6 अक्टूबर को सभी दुकानें बंद रखने के साथ चक्का जाम का आह्वान किया गया। 7 अक्टूबर को जिला मुख्यालय में सांकेतिक धरना दिया जाएगा तथा उपायुक्त के माध्यम से केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार को ज्ञापन सौंपा जाएगा। समिति ने लोगों से आवश्यक सेवाओं को बंद से मुक्त रखते हुए आंदोलन को सफल बनाने में सहयोग की अपील की है। कार्यक्रम के दौरान प्रदर्शनकारियों ने ओबीसी के अधिकारों और सामाजिक भागीदारी से जुड़े मुद्दों को लेकर नारेबाजी भी की। केंद्रीय पिछड़ा जाति संघर्ष समिति के आह्वान पर मंगलचार को सिमडेगा जिला भी बंद रहा। बंद का व्यापक असर जिला मुख्यालय से लेकर प्रखंडों तक देखने को मिला। इस कारण कई दुकानें बंद रहीं। जबकि बसों और छोटे यानों वाहनों के पछि थकने से लोगों को आवागमन में भारी परेशानी उठानी पड़ी। अहले सुबह से ही समिति के जिला अध्यक्ष रामजी यादव के नेतृत्व में समाज के लोग एनएच-143 पर उतर गए और सड़क जाम कर दिया, जिससे क़रीब तीन घंटे तक मुख्य मार्ग पर आवागमन बाधित रहा। हालांकि सुरक्षा मिलने पर थाना प्रभारी और गैरल अधिकारी मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों को समझाकर सड़क जाम हटवाया। जिसके बाद मार्ग पर आवागमन शुरू हुआ। जिला अध्यक्ष रामजी यादव ने कस कि ओबीसी समाज अब अपने अधिकारों को लेकर पीछे हटने वाला नहीं है। सरकार जब तक मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लेती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि जल्दतर पड़ी तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा।

हनफी कानून में बेटी के बालिंग होने तक मुस्लिम मां को कस्टडी का प्राथमिक अधिकार, हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के फैसले को किया रद्द, गार्जियनशिप के मामले को नोटिस वाले चरण से फिर से शुरू करने का निर्देश

01 रांची, एजेंसी। झारखंड हाई कोर्ट की जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस संजय प्रसाद की खंडपीठ ने नाबालिंग बेटी की कस्टडी से जुड़े एक अहम मामले में कहा है कि हनफी मुस्लिम कानून के तहत बेटी के बालिंग होने तक उसकी कस्टडी पर मां का प्राथमिक अधिकार होता है। हालांकि, यह अधिकार पूर्ण नहीं है और हर स्थिति में बच्चे का कल्याण ही अदालत के लिए सबसे अहम कसौटी रहेगा। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि बच्चे की कस्टडी जैसे संवेदनशील मामले में दोनों पक्षों को सुने बिना एक्तरफा फैसला नहीं किया जा सकता। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता कृपा शंकर नंदा जबकि प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता ए।के।साहनी और कृष्णा सागर ने पक्ष रखा। मामला रांची फैमिली कोर्ट से जुड़ा है।



पेपर लीक का ‘इनसाइड कनेक्शन’,

अभ्यर्थी राहुल के पास कैसे पहुंचा गोपनीय प्रश्नपत्र

रांची, एजेंसी। जेएसएससी-सीजीएल पेपर लीक मामले की जांच में सामने आई राहुल कुमार की भूमिका ने परीक्षा की गोपनीय व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सीआईडी के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, राहुल खुद जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा का अभ्यर्थी था, लेकिन इसके बावजूद वह उस एजेंसी से जुड़ा था, जिसे परीक्षा के प्रश्नपत्रों की प्रिंटिंग और अन्य गोपनीय काम सौंपे गए थे। जांच में उसकी मानेसर स्थित प्रिंटिंग फैसिलिटी में मौजूदगी, गोपनीय प्रश्नपत्रों तक पहुंच और परीक्षा से पहले वाट्सएप के जरिए प्रश्न-उत्तर सामग्री के आदान-प्रदान की बात सामने आई है। सीआईडी ने अदालत को बताया कि राहुल कुमार आईसीएन से जुड़ा था। आईसीएन को जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा के प्रश्नपत्रों की प्रिंटिंग, ओएमआर प्रिंटिंग और अन्य गोपनीय परीक्षा संबंधी काम सौंपे गए थे। सीआईडी के मुताबिक, राहुल खुद उसी परीक्षा का अभ्यर्थी था। इसके बावजूद उसके पास परीक्षा की गोपनीय सामग्री तक पहुंच थी और वह मानेसर की प्रिंटिंग फैसिलिटी में प्रश्नपत्रों की प्रिंटिंग, निगरानी और पैकेजिंग की प्रक्रिया में शामिल रहा। सीआईडी ने राहुल के मोबाइल नंबर के सीडीआर और लोकेशन के साथ-साथ फैक्ट्री रजिस्टर को भी उसकी मौजूदगी की पुष्टि करने वाला महत्वपूर्ण साक्ष्य बताया है। जांच का सबसे अहम हिस्सा परीक्षा से पहले



प्रश्नपत्र से संबंधित सामग्री के वाट्सएप के जरिए आदान-प्रदान का है। अभियोजन के अनुसार, परीक्षा से कुछ समय पहले प्रश्नों के सेट वाट्सएप पर भेजे गए। राहुल ने कथित तौर पर यह सामग्री प्राप्त की और प्रश्न तथा उत्तर आगे भी भेजे। सीआईडी का दावा है कि राहुल को इस सामग्री के गोपनीय होने की जानकारी थी, इसके बावजूद वह इसके आदान-प्रदान में शामिल रहा। जांच के मुताबिक, राहुल की भूमिका केवल पेपर हासिल करने वाले अभ्यर्थी तक सीमित नहीं थी, बल्कि वह उस व्यवस्था की कड़ी के रूप में सामने आया, जिसके जरिए परीक्षा से पहले

प्रश्न-उत्तर सामग्री दूसरे लोगों तक पहुंची। वहीं राहुल की ओर से अदालत में कहा गया कि उसके मोबाइल से मिले वाट्सएप चैट सामान्य पढ़ाई और तैयारी से संबंधित थे। उसने यह भी दावा किया कि उसने किसी तीसरे व्यक्ति को प्रश्नपत्र या उत्तर कुंजी नहीं भेजी और उसके खिलाफ कोई आर्थिक लाभ लेने का प्रमाण नहीं है। लेकिन अभियोजन ने इन दलीलों का विरोध करते हुए कहा कि वाट्सएप चैट, अन्य आरोपियों के बयान और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को एक साथ देखने पर राहुल की भूमिका सामने आती है। अदालत ने भी उपलब्ध सामग्री के

40 पार कोलकर्मियों की हर साल मेडिकल जांच का प्रस्ताव,

यूनियनों ने जताया विरोध, आंदोलन की चेतावनी

धनबाद, एजेंसी। कोल इंडिया में कोलकर्मियों की मेडिकल जांच को लेकर प्रस्तावित नई व्यवस्था पर विवाद शुरू हो गया है। खदानों में कार्यरत कर्मचारियों की आवधिक चिकित्सा जांच यानी ऋद्ध को अब सालाना करने की तैयारी है। वहीं 40 वर्ष की उम्र पूरी करने वाले कर्मचारियों के लिए भी हर साल स्वास्थ्य जांच का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। यूनियनों ने इस प्रस्ताव पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि मेडिकल जांच की आड़ में कर्मचारियों की संख्या कम करने की कोशिश की जा सकती है। हालांकि, ये यूनियन नेताओं के आरोप हैं और इस पर प्रबंधन का पक्ष सामने आना बाकी है। कोयला खदानों में काम करने वाले कर्मचारियों की सेहत की निर्यामित निगरानी को लेकर कोल इंडिया नई व्यवस्था की तैयारी में है। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत फिलहाल अधिकतम पांच साल के अंतराल पर होने वाली आवधिक चिकित्सा जांच को वार्षिक करने की प्रक्रिया चल रही है। इसके अलावा 40 वर्ष की उम्र पूरी करने वाले कोलकर्मियों के लिए हर साल स्वास्थ्य जांच का प्रावधान भी प्रस्तावित किया गया है। यानी उम्र बढ़ने के साथ कर्मचारियों की स्वास्थ्य स्थिति पर नियमित निगरानी रखने की व्यवस्था तैयार की जा रही है। लेकिन इस प्रस्ताव के सामने आते ही यूनियनों ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। जेबीसीसीआई के पूर्व सदस्य बिदेश्वरी प्रसाद ने आरोप लगाया कि प्रबंधन मैनपावर कम करने की



दिशा में आगे बढ़ रहा है। उनका कहना है कि हर साल मेडिकल जांच के बाद कर्मचारियों को धीरे-धीरे अस्वस्थ घोषित किए जाने की आशंका है। उनके मुताबिक, यदि किसी कर्मचारी को अस्वस्थ घोषित कर इय्टी से अलग किया जाता है तो उसके वेतन के साथ-साथ नौकरी से जुड़े दूसरे लाभ भी प्रभावित हो सकते हैं। उन्होंने बोस, ग्रेच्युटी और पीएफ जैसी सुविधाओं पर भी असर पड़ने की आशंका जताई। वेतन पर असर का मतलब जिन्हें संडे या ओटी मिलती है उस पर भी सीधा असर पड़ेगा। बिदेश्वरी प्रसाद ने कहा कि मामला अभी शुरूआती दौर में है और कर्मचारी हित में सभी यूनियनों को इस प्रस्ताव का विरोध करना चाहिए। उनका आरोप है कि मेडिकल जांच के जरिए धीरे-धीरे मैनपावर कम करने की कोशिश की जा सकती है। हालांकि, यह

बिहार में घर के बाहर खड़े प्रॉपर्टी डीलर को मारी गोलियां, 10 घंटे बाद भी बदमाशों को नहीं पकड़ सकी पुलिस

मोजपुर, ऐजेंसी। बिहार के मोजपुर ज़िले के गजरागंज ओपी क्षेत्र के चौकीपुर गांव में मंगलवार देर शाम दशियारबंद बदमाशों ने घर के बाहर खड़े प्रॉपर्टी डीलर को गोली मार दी। बदमाशों ने बेहद करीब से उस पर दो गोलियां चलाईं। गोलीबारी में चौकीपुर गांव निवासी कमल यादव के 40 वर्षीय पुत्र राज कुमार घायल हो गए। एक गोली उनकी बाईं जांघ और दूसरी बाईं तरफ पेट में लगी। गंभीर लव्हात में परिजन उन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल ले गए, जहां से बेहतर इलाज के लिए आरा के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल उनका इलाज जारी है। फायरिंग की घटना के बाद चौकीपुर गांव और आसपास के इलाके में दहशत का माहौल है। सूचना मिलने पर गजरागंज ओपी पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल की जांच शुरू कर दी। सदर एसडीपीओ। सुशील कुमार ने बताया कि राज कुमार को दो गोलियां लगी हैं। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज की जांच कर रही है, ताकि हमलावरों की पहचान की जा सके। घटना की जांच के लिए एमएसएल की टीम को भी मौके पर बुलाया गया। टीम ने घटनास्थल से जरूरी साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस अब फायरिंग के पीछे की वजह और आरोपियों की पहचान का प्रत लगाने में जुटी है।

बिहार में इस्टबिन घोटाला मामला: पटना हाईकोर्ट ने सरकार को हलफनामा दायर करने का दिया निर्देश

पटना, ऐजेंसी। पटना हाईकोर्ट में कथित इस्टबिन घोटाले से सम्बन्धित जनहित याचिका पर सुनवाई की गई। कोशलेश कुमार की जनहित याचिका पर चौफ जस्टिस वी कामेश्वर राव की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को हलफनामा दायर करने के लिए 3 नवंबर, 2026 तक की मौलत दी है। बिहार के सरकारी सस्पिटल में बायो मेडिकल वेस्ट को नष्ट करने के लिए खरीदे गए उपकरणों में बड़े पैमाने पर हेरफेर का आरोप लगाते हुए ये जनहित याचिका पटना हाईकोर्ट में दायर की गई। जनहित याचिका कोशलेश कुमार द्वारा दायर की गई है। याचिकाकर्ता के वरीय अधिवक्ता रंजीव कुमार मिश्र ने बताया कि पिछली सुनवाई 8 सितंबर, 2026 को हुई थी। राज्य सरकार को इस मामले पर जवाब दायर करने का आदेश कोर्ट ने दिया था। कोर्ट की याचिकाकर्ता के अधिवक्ता रंजीव कुमार मिश्र ने बताया कि बीएमएसएससीएल ने राज्य के अस्पतालों में 75 और 45 लीटर के माइक्रोवेव इस्टबिन और इसमें कचरा रखने के लिए 75 और 45 लीटर के वायोडिग्रेडेबल बैग के आपूर्ति के लिए निविदा निकाला। लखनऊ की एक कंपनी को निविदा दे दिया गया। इस जनहित याचिका में ये आरोप लगाया गया कि 75 लीटर वाला एक माइक्रोवेव खरीद 15490 रुपये की गयी, जबकि बाजार में इसकी कीमत मात्र 1550 रुपये है। 45 लीटर वाली इस्टबिन 11474 रुपये में खरीदी गई, जिसकी बाजार में कीमत 1162 रुपये बताई गई। इस जनहित याचिका ये भी आरोप लगाया गया कि 75 लीटर का वायोडिग्रेडेबल बैग 98 रुपए में खरीदा गया, जबकि सामान्य कीमत साढ़े 8 रुपये है। वहीं 45 लीटर का बैग 69 रुपये में खरीदा गया, जबकि इसकी वास्तविक कीमत पौने 6 रुपये बतायी गई। इस जनहित याचिका में बताया गया कि जून, 2024 से 18 अप्रैल, 2026 के बीच इसकी खरीदारी 57 अड़र से की गई। इस निविदा में सात कंपनियों भाग लिया था। इनमें ये आरोप लगाया गया था कि इन चार अइटम की खरीदारी 18 फीसदी जीएसटी के साथ लगभग 307 करोड़ रुपये में हुई। इनको बेचने वाली चार फर्मों से कोटेशन लेने पर कुल नुसखा 18 फीसदी जीएसटी लगभग 29 करोड़ रुपए होता है। इन आरोपों पर अगली सुनवाई में राज्य सरकार का जवाब आने के बाद स्थिति स्पष्ट होगी। इस मामले पर 3 नवंबर, 2026 को सुनवाई होगी है।

बिहार में युवक को 24 बार चाकू घोंपा, हत्या के बाद शव को नदी किनारे फेंका

मोतिहारी, ऐजेंसी। बिहार के मोतिहारी में सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जिसने पूरे इलाके को दहला दिया है। अपराधियों ने एक युवक को उसके घर से बुलाया और फिर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। युवक के शरीर पर चाकू से करीब दो दर्जन बार हमले किए गए हैं। हत्या के बाद शव को रेवता नदी किनारे फेंक दिया गया। मंगलवार सुबह शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। घटना तुरकौलिया थाना क्षेत्र के जयसिंहपुर की है। मृतक की पहचान जयसिंहपुर के रिक्रुअ बाजार निवासी भुलन साह के पुत्र दीपक कुमार के रूप में हुई है। परिजनो ने बताया कि सोनवार की रात करीब आठ बजे तुरकौल साह का पुत्र और दो अन्य युवक दीपक को उसके घर से बुलाकर अपने साथ ले गए थे। दीपक उन युवकों के साथ घर से निकला था लेकिन इसके बाद वह वापस नहीं लौटा। रात बीतने के बाद भी जब दीपक घर नहीं पहुंचा तो परिवार के लोग परेशान हो गए। इसी बीच मंगलवार सुबह रेवता नदी किनारे एक युवक का शव मिलने की सूचना इलाके में फैल गई। खबर मिलते ही मृतक के परिजन भी मौके पर पहुंचे। शव की स्थिति देखकर परिवार के लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। शव की शिनाख्त दीपक के रूप में हुई। उसके शरीर पर चाकू से किए गए कई गहरे जख्म थे। ‘छह लड़के मेरे बेटे को रात में बुलाकर ले गए थे। रात में जब घर वापस नहीं लौटा तो हमलोग परेशान हो गए। सुबह उठे तो मालूम हुआ कि किसी की लाश नदी किनारे पड़ी है। गए तो देखे मेरा दीप दीपक था। मेरापुत्र में बोर का काम करता था। शरीर पर चाकू से कई बार हमला हुआ है। सुनार और दिलखुश ने ही मिलकर हमारा दिया उसको घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर गांधीगों की भारी भीड़ जुट गई। सूचना मिलने पर सदर डीएसपी दिलीप कुमार, तुरकौलिया थानाध्यक्ष रंजीत कुमार और दारोगा नवीश राज पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे।

अनंत सिंह-नीरज कुमार विवाद पर बिहार के डिप्टी सीएम बोले- पार्टी ले रही संज्ञान

ललन सिंह की पहल से मिला रास्ता

पटना, ऐजेंसी। अनंत सिंह और नीरज कुमार के बीच चल रहे विवाद को लेकर जेडीयू ने अपना रुख साफ किया है। उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने केन्द्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह की पहल का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि विवाद को सुलझाने की दिशा में एक रास्ता मिला है।

विजय चौधरी ने कहा कि ललन सिंह ने इस मामले में जो भी बातें कही हैं, पार्टी उनका संज्ञान ले रही है। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि विवाद से जुड़े दूसरे पहलुओं पर भी पार्टी स्तर पर विचार किया जा रहा है।

विजय कुमार चौधरी ने कहा कि केन्द्रीय मंत्री ललन सिंह ने विवाद को सुलझाने की दिशा में पहल की है। इसके लिए उन्होंने ललन सिंह को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि ललन सिंह की पहल के बाद इस मामले को सुलझाने का रास्ता मिला है। पार्टी उनके बयान और पहल को गंभीरता से देख रही है।

पत्रकारों ने विजय चौधरी से ललन सिंह के उस बयान को लेकर सवाल किया, जिसमें उन्होंने अनंत सिंह और नीरज कुमार के पुराने विवाद को



लेकर प्रदेश नेतृत्व की चूक की बात कही थी।

इस पर विजय चौधरी ने कहा कि पार्टी इन सभी मामलों का संज्ञान ले रही है। उन्होंने किसी कार्रवाई को लेकर नहीं कहा, उनके बयान से साफ है कि पार्टी विवाद से जुड़े पूरे मामले को देख रही है। विजय चौधरी ने यह बातें मंगलवार को जेडीयू प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में कहीं।

प्रेस वार्ता के दौरान विजय चौधरी ने बिहार में बाढ़ की स्थिति को लेकर भी

लापरवाही करने पर बिहार के जल संसाधन विभाग का एक्शन, 7 अभियंता निलंबित

पटना, ऐजेंसी। नेपाल और उत्तर प्रदेश में हुई भारी बारिश के बाद गंडक नदी में आई भीषण बाढ़ के दौरान तटबंधों की सुरक्षा और आकस्मिक कार्रवाई में कमी बरतने वाले अभियंताओं पर जल संसाधन विभाग ने सख्त कार्रवाई शुरू की है। स्थल निरीक्षण और प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर विभाग ने कुल 8 अभियंताओं के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही शुरू करने का निर्णय लिया है।

विभाग ने 7 अभियंताओं को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया है। निलंबित अभियंताओं में संतोष कुमार प्रभावकर, कार्यपालक अभियंता, छपरा; मो। साजिद इकबाल, कार्यपालक अभियंता, गोपालगंज; सुनील कुमार, सहायक अभियंता, छपरा; विनोद कुमार, सहायक अभियंता, छपरा; मो। जादेव अंसारी, सहायक अभियंता, गोपालगंज;



चंद्रशेखर कुमार, कनीय अभियंता, छपरा और विकास कुमार, कनीय अभियंता, गोपालगंज शामिल हैं।

इसके अलावा कुमार मनोज गुप्ता, मुख्य अभियंता, मुजफ्फरपुर के विरुद्ध भी विभागीय कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया गया है। उन पर चंपारण तटबंध के क्षतिग्रस्त होने और उसके बाद की जाने वाली आकस्मिक प्रतिक्रिया में शिथिलता एवं लापरवाही बरतने का आरोप है।

नेपाल और उत्तर प्रदेश में भारी बारिश के कारण गंडक नदी का जलस्तर बिहार में बागहा, डुमरियाघाट, रेवाघाट और लालगंज में अपने पुराने उच्चतम स्तर को पार कर गया था।

बिहार के सिकंदरपुर थाना क्षेत्र में मंदिर में मिला महंत का शव

मुजफ्फरपुर, ऐजेंसी। बिहार के मुजफ्फरपुर से सनसनीखेज मामला सामने आया है। सिकंदरपुर थाना क्षेत्र में बुधवार को मंदिर के 80 वर्षीय महंत की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बालूघाट रोड स्थित मंदिर परिसर में महंत महावीर दास का शव फर्श पर पड़ा मिला। मंदिर के गेट अंदर से बंद था।

ऐसे में उनकी मौत को लेकर कई तरह की आशंकाएं जताई जा रही हैं। हालांकि, मौत की वास्तविक वजह अभी स्पष्ट नहीं हुई है। सुबह मंदिर का दरवाजा नहीं खुला और पूजा-पाठ शुरू नहीं हुआ तो स्थानीय लोगों को संदेह हुआ। लोगों ने मौके पर पहुंचकर देखा तो मंदिर परिसर के अंदर महंत का शव फर्श पर पड़ा था। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई।

मृतक की शिनाख्त महावीर दास के रूप में हुई है। बताया जाता है कि महंत महावीर दास लंबे समय से इसी मंदिर परिसर में रह रहे थे। वह मंदिर की देखरेख करने के साथ पूजा-पाठ भी करते थे। वह मंदिर परिसर में अकेले रहते थे।

सूचना मिलने पर सिकंदरपुर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल की जांच शुरू की।



थाना प्रभारी राकेश मोहन ने बताया कि मंदिर परिसर में महंत का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला है। मंदिर का गेट अंदर से बंद था और शव फर्श पर पड़ा मिला। मौत की वास्तविक वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा।

'पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने के लिए सस्स्टीम को सूचना दी है। टीम के पहुंचने के बाद घटनास्थल की जांच और साक्ष्य संकलन किया जाएगा। फिलहाल पुलिस बीमारी, जहरीले पदार्थ के सेवन और अन्य संभावित कारणों को ध्यान में

बिहार

किया गया है। इसके अलावा एक मुख्य अभियंता के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जा रही है। एक सहायक अभियंता और एक कार्यपालक अभियंता को शो-काॅज नोटिस जारी किया गया है।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ से परेशान लोगों की मुश्किलें दूर करने में अगर कोई अधिकारी लापरवाही बरतता है, तो सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी।

नदियों में बढ़ती गाद की समस्या को लेकर भी विजय चौधरी ने सरकार का रुख बताया। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार इस चिंता से केंद्र सरकार को लगातार अवगत कराती रही है।

फरक्का जलसंधि को लेकर भी राज्य सरकार अपनी चिंता केंद्र के सामने रखती रही है। विजय चौधरी ने कहा कि इस दिशा में केंद्र सरकार की ओर से पहल की जा रही है।

जेडीयू प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में ऊर्जा मंत्री शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल भी मौजूद रहे। उनके अलावा विधान परिषद सदस्य संजय सिंह उर्फ गांधीजी, डॉ। नवीन आर्य और अंजुम आरा भी मौजूद थीं।

बाढ़ प्रभावित परिवारों को 12 अक्टूबर को राहत राशि वितरित होगी' समीक्षा बैठक के बाद सीएम ने दी जानकारी

पटना, ऐजेंसी। बिहार में बाढ़ से हुई तबाही और राहत-बचाव कार्यों को लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने समीक्षा बैठक की। बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से



सोन, घाघरा, कोसी और पुनपुन नदियों में कई स्थानों पर पहले के रिकॉर्ड से अधिक जलस्तर दर्ज किया गया। दूसरे चरण में भारी बारिश के चलते गंडक नदी के चार स्थानों पर उच्चतम जलस्तर दर्ज हुआ।बाढ़ के दौरान पश्चिम चंपारण, गोपालगंज और सारण जिलों में छह स्थानों पर तटबंधों को नुकसान पहुंचा। समीक्षा बैठक में अधिकारियों ने बाढ़ के दौरान किए गए राहत और बचाव कार्यों की भी जानकारी मुख्यमंत्री को दी।

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि गंगा, गंडक और सोन नदियों में इस वर्ष पिछले वर्षों की तुलना में काफी अधिक पानी आया, जिससे बाढ़ की स्थिति गंभीर हुई। उन्होंने नदी तल में

बिहार में ‘मेड इन पाकिस्तान’ चादरें बेचते दिखे दो सदिग्ध युवक, पुलिस को सूचना मिलते ही फरार

मोतिहारी, ऐजेंसी। बिहार के मोतिहारी शहर के रघुनाथपुर इलाके में दो संदिग्ध युवकों द्वारा कथित तौर पर ‘मेड इन पाकिस्तान’ लिखी चादरें बेचने का मामला सामने आया है। घटना के बाद स्थानीय लोगों में तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। जानकारी के अनुसार, मंगलवार को रघुनाथपुर इलाके में दो युवक चादर बेच रहे थे।बताया जा रहा है कि दोनों युवक महंगी चादरें बेहद कम कीमत पर बेच रहे थे। एक से दो सौ रुपये में चादर मिलने की बात सुनकर कई स्थानीय लोगों ने उनसे चादरें खरीद भी लीं। इसी दौरान कुछ लोगों को दोनों युवकों की गतिविधियां संदिग्ध लगीं। स्थानीय लोगों के मुताबिक, दोनों युवक मोतिहारी के रहने वाले नहीं लग रहे थे।

स्थानीय लोगों के अनुसार, पुलिस को सूचना दिए जाने के बाद दोनों युवकों को मौके पर रोककर रखने की बात कही गई थी। लेकिन इसी बीच दोनों युवक अचानक वहां से गायब हो गए। उनके अचानक चले जाने के बाद इलाके में चर्चा और संदेह और बढ़ गया।सदर डीएसपी दिलीप कुमार ने कहा कि जिस व्यक्ति ने यह चादर खरीदी थी, उसने चादर पर लिखा देखा। इसके बाद उसने तुरंत 112 नंबर पर कॉल कर पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और चादर को जब्त कर लिया।"बताया जा रहा है कि यह चादर किसी दुकान में खुले बाजार में नहीं बेची गई थी, बल्कि एक फेरी वाले से खरीदी गई थी। अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि फेरी वाला कौन था, चादर उसके पास कहां से आई और वह इसे कहां से लेकर आया था। फिलहाल पुलिस ने चादर को ज्वार कर जांच शुरू कर दी है। जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट हो जाएगा कि चादर वास्तव में पाकिस्तान से आई है या इसके पीछे कोई और कहानी है।

बाढ़ प्रभावित परिवारों को 12 अक्टूबर को राहत राशि वितरित होगी' समीक्षा बैठक के बाद सीएम ने दी जानकारी

जमा होने वाली गाद को भी बाढ़ की प्रमुख वजहों में शामिल किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार देश का पहला राज्य है, जिसने गाद प्रबंधन को लेकर नीति बनाई है।

मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को बाढ़ से हुए नुकसान का विस्तृत आकलन करने का निर्देश दिया।

उन्होंने कहा कि प्रभावित क्षेत्रों में राहत, पुनर्वास और जरूरी विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए नुकसान की रिपोर्टें जल्द तैयार होनी चाहिए। आपदा प्रबंधन विभाग को सभी संबंधित विभागों से क्षति और पुनर्स्थापन पर आने वाले खर्च का आकलन कराकर रिपोर्ट देने को कहा गया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि बाढ़ के दूसरे चरण से प्रभावित परिवारों को 12 अक्टूबर 2026 को अनुग्रहिक राहत राशि दी जाएगी। उन्होंने जलनिकासी के बाद प्रभावित इलाकों में पैदा होने वाली संभावित समस्याओं को देखते हुए पहले से जरूरी इंतजाम करने के निर्देश भी दिए।

एक साल से नहीं उठा कचरा, सड़क किनारे लगे ढेर से दुर्गंध, नवरात्र से पहले बड़ी परेशानी

पटना, ऐजेंसी। फुलवारी

शरीफ प्रखंड की सकरैचा पंचायत के वार्ड संख्या 11 स्थित नूरमोईउद्दीनपुर में करीब एक साल से घरेलू कचरे का उठाव बंद है। इससे सड़क किनारे और खाली जगहों पर कचरे का ढेर जमा हो गया है। कचरे से निकलने वाली दुर्गंध के कारण स्थानीय लोगों को परेशानी हो रही है। नवरात्र, दीपावली और छठ से पहले लोगों ने जल्द सफाई की मांग की है।

नूरमोईउद्दीनपुर में शिवनगर बांध के पास पुनपुन स्टैंड के समीप जगह-जगह घरेलू कचरा जमा है। स्थानीय लोगों के अनुसार लंबे समय से कचरा नहीं उठने के कारण स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। आसपास रहने वाले लोगों को कचरे

से निकलने वाली दुर्गंध के कारण परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले पांच वर्षों में करीब छह महीने तक ही घरेलू कचरे का उठाव नियमित रूप से हुआ। इसके बाद व्यवस्था धीरे-धीरे बंद होती गई। पिछले करीब एक वर्ष से कचरा उठाव पूरी तरह ठप है। इससे लोगों के सामने घरों से निकलने वाले कचरे को रखने की समस्या खड़ी हो गई है। वार्ड का इलाका शहरी क्षेत्र की तरह विकसित हो चुका है। ऐसे में लोगों के पास कचरा फेंकने के लिए कोई वैकल्पिक स्थान नहीं है। कचरा उठाव की व्यवस्था नहीं होने के कारण घरों से निकलने वाला कचरा सड़क किनारे और खाली जगहों पर जमा हो रहा है।

पटना में प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर कर लें ये काम नहीं तो लगेगा 100 प्रतिशत जुर्माना, 31 दिसंबर तक मौका

पटना, ऐजेंसी। बिहार की राजधानी पटना में संपत्ति कर को लेकर नगर निगम ने सख्त रुख अपनाया है। डोर-टू-डोर सर्वेक्षण में कर के दायरे से बाहर मिली संपत्तियों के मालिकों को 31 दिसंबर 2026 तक कर निर्धारण कराने का मौका दिया गया है। निर्धारित समयसीमा खत्म होने के बाद जनवरी 2027 से ऐसी संपत्तियों पर 100 फीसदी जुर्माना लगाया जाएगा।

नागरिकों की सुविधा के लिए पटना नगर निगम की ओर से वार्डवार विशेष कर निर्धारण शिविर लगाए जा रहे हैं। नगर आयुक्त यशपाल मौपणा ने सभी अंचलों को तय अवधि तक विशेष शिविर आयोजित करने का निर्देश दिया है।

इन शिविरों में नागरिक नया संपत्ति कर निर्धारण, पुनर्निर्धारण, कर में संशोधन या परिवर्तन और बकाया कर का भुगतान करा सकेगें। निगम के अनुसार, नागरिक अपनी सुविधा के मुताबिक किसी भी नजदीकी विशेष शिविर में जाकर इन सेवाओं का लाभ ले सकते हैं।

नगर निगम के डोर-टू-डोर सर्वेक्षण के दौरान कई ऐसी संपत्तियां चिन्हित की गई हैं, जिनका अब तक संपत्ति कर निर्धारण नहीं हुआ है। इन संपत्तियों के मालिकों को विशेष शिविरों के माध्यम से कर के दायरे



में आने की प्रक्रिया पूरी करने का अवसर दिया जा रहा है। पहले चरण में पाटलिपुत्र और नूतन राजधानी अंचल में विशेष शिविर शुरू किए गए हैं। शुरुआती दो दिनों में दोनों अंचलों में 60 से अधिक संपत्तियों का नया कर निर्धारण हुआ। इस दौरान 16 संपत्तियों में कर संशोधन और 6 संपत्तियों का पुनर्निर्धारण भी किया गया।

विशेष शिविरों के दौरान 211 संपत्तियों से करीब 14 लाख रुपये का संपत्ति कर भी वसूला गया। निगम का कहना है कि शिविरों के जरिए नागरिकों को स्थानीय स्तर पर सुविधा मिल रही है और राजस्व संग्रह में भी तेजी आई है।

7 अक्टूबर को नूतन राजधानी अंचल के वार्ड संख्या-3 स्थित सबजपुरा के वार्ड पार्षद कार्यालय में और पाटलिपुत्र अंचल के वार्ड संख्या-22 स्थित अशोक राजपथ के गेट संख्या-93 पर शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद, 8 से 10 अक्टूबर तक नूतन राजधानी अंचल के वार्ड संख्या-11 स्थित हरनीचक के वार्ड पार्षद कार्यालय में और पाटलिपुत्र अंचल के वार्ड संख्या-22बी स्थित कुर्जी में बैंक ऑफ बड़ौदा के पास वाले वार्ड पार्षद कार्यालय में शिविर लगाए जाएंगे।

पीएम मोदी 25 अक्टूबर को काशी में जेन-जी से करेंगे संवाद, जीस और टीशर्ट में आएंगे 30 हजार युवा

वाराणसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 अक्टूबर को काशी आएंगे। वह नमो घाट जाकर एयर थो देखेंगे फिर जेन जी से संवाद करेंगे। इसके लिए बीएचयू या फिर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में व्यवस्था की जा रही है। जेन जी संवाद में 18 से 25 साल के करीब 30 हजार युवा हिस्सा लेंगे। सब जीस और टीशर्ट पहनकर आएंगे।भाजपा नेताओं के मुताबिक, पीएम नरेंद्र मोदी 25 अक्टूबर की सुबह ही काशी आ जाएंगे। वह नमो घाट जाएंगे जहां राफेल सहित 90 फाइटर जेट करतब दिखाएंगे। फाइटर जेट बाबतपुर एयरपोर्ट और प्रयागराज से उड़ान भरेंगे। पीएम के साथ हैं रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, सीएम योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल, सीडीएस, सीनो सेनाओं के प्रमुख मौजूद रहेंगे। इसकी तैयारी में भाजपा की क्षेत्रीय, जिला और महनगर इकाई जुट गई हैं। सुरक्षा व्यवस्था भी परखी जा रही है। काशी में एयर थो 22, 24 और 25 अक्टूबर को होना है। पीएम अतिथि दिन एयर थो देखेंगे।

ब्रेकियल प्लेवसस इंजरी से जुड़ा रहे मरीज का सफल ऑपरेशन

आगरा। एसएन मेडिकल कॉलेज के प्लास्टिक सर्जरी विभाग के डॉक्टरों ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। सड़क हादसे में बुरी तरह प्रभावित हुए 21 वर्षीय युवक तुलाराम के दाहिने हाथ की नसों को माइक्रोसर्जरी के जरिये फिर से जीवनदान दिया है। ब्रेकियल प्लेवसस नर्व ट्रान्सफर सर्जरी से युवक के कबो की रुकी हुई गतिविधि को सफलतापूर्वक बहाल कर दिया गया है।विभाग की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. श्रीप्रिया पीपी और एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. प्रणय सिंह कटोदिया के नेतृत्व में इस जटिल माइक्रोसर्जिकल प्रक्रिया को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया। इस सर्जरी का मुख्य उद्देश्य मरीज के कबे और हाथ को बाइर की ओर उठाने की धमता को दोबारा शुरू करना था। इस पूरी सर्जिकल प्रक्रिया में रेजिडेंट डॉक्टर डॉ. अर्पिता और डॉ. मोहित ने अपना महत्वपूर्ण सहयोग दिया। वहीं, एनेस्थीसिया (निद्रावैधान) टीम की निगरानी में अमृता गुप्ता, डॉ. दीपिका चौबे और डॉ. विनिता लिटटन ने बेखुबी निभाई। एसएन मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. प्रशांत गुप्ता ने पूरी चिकित्सीय टीम की सराहना करते हुए कहा कि यह संश्लेषण मरीजों को उच्चस्तरीय और उन्नत चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। डॉक्टरों के अनुसार, सफल सर्जरी के बाद अब मरीज की हालत में लगातार सुधार हो रहा है।

रामायण की प्रदर्शनी देख खुद ही ठहर जाएंगे कदम, इसमें है कुछ बेहद खास

आगरा। झालर्न की सतरंगी रोशनी से जगमगाती जनकपुरी की सड़कों पर मंगलवार को भारी जनसैलाब उमड़ पड़ा। क्षेत्र में रामायण के विभिन्न दृश्यों और घटनाक्रमों को जीवंत करती सांकेतिक आकर्षण का केंद्र रही। इसके अलावा होली पब्लिक स्कूल चौराहे पर रम्या नव्य शंख भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता नजर आया। जनकपुरी महासंघ के मेले का सा मनमोहक दृश्य नजर आया। जगमगाती रोशनी के बीच सड़कों पर उमड़ती भीड़ को देखकर ऐसा लगा रल था कि मानो पूरा शहर ही जनकपुरी देखने ने के लिए आ गया हो। क्षेत्र में भगवान श्रीराम के जीवन से जुड़ी विशेष प्रदर्शनियों को देखकर लोगों के कदम स्वतः द्धर जाते और वे इन पलों को अपने मोबाइल में कैच करते दिखाई दिए। भारी भीड़ के कारण यातायात व्यवस्था पूरी तरह परेशान गई। स्थिति यह रही कि जनक महल तक पहुंचने में लोगों को घंटों लग गए। वाहनों का आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित नहीं होने के कारण हुजुमी और महिलाओं को सबसे अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जनक महल के पास रास्ता जाम होने के कारण दोनों तरफ से वाहन उल्टी-सीधी दिशा में निकलने लगे, जिससे सड़क पर लंबा जाम लग गया और लोगों को परेशानी उठानी पड़ी।

मौत से पहले का बयान बन सकता है अहम साक्ष्य, संभव हो तो डिजिटल रिकॉर्डिंग पर जोर

लखनऊ। मौत की आशंका वाले मामले में पीडित का बयान जांच के लिए अहम साक्ष्य बन सकता है। ऐसे में उसका बयान तत्काल दर्ज किया जाना चाहिए और संभव हो तो उसकी डिजिटल रिकॉर्डिंग भी कराई जानी चाहिए। उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस के संस्थापक निदेशक डॉ. जीके गोस्वामी ने मंगलवार को प्रांतीय सिविल सेवा (पीएससी) 2025 बैच के 38 प्रशिक्षु अधिकारियों को फॉरेंसिक विज्ञान की बाथीकिया समझाते हुए यह बात कही। कानपुर रोड के दरोगाखेड़ा स्थित संस्थान के भ्रमण पर पहुंचे प्रशिक्षु अधिकारियों ने डीएनए और ड्रग लैब का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्हें फॉरेंसिक विज्ञान में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीकों और उनकी प्रयोगशाला की जानकारी दी गई। डॉ. गोस्वामी ने कहा कि फॉरेंसिक साइंस के माध्यम से सच्चाई को वैज्ञानिक रूप से कानून के समक्ष लाकर न्याय दिलाने में सहयोग करना संस्थान का मूल उद्देश्य है। पीडित में सिविल सेवा का कार्य बेहद चुनौतीपूर्ण है और इसमें त्याग व समर्पण की जरूरत होती है। अधिकारियों को विषम परिस्थितियों से निपटने के लिए मानसिक रूप से सदैव तैयार रहना चाहिए।उन्होंने कहा कि कानून और विज्ञान का संगम ही फॉरेंसिक विज्ञान है और फॉरेंसिक एक विज्ञान है। साइबर और फॉरेंसिक विज्ञान आज जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं। आधुनिक तकनीक पर बढ़ती निर्भरता के कारण व्यक्ति हर जगह अपना डिजिटल फुटप्रिंट छोड़ता है। निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक धिरेजीव ब्रध्दजी, अतुल यादव, पलक अनेजा, संथिल शिव सुब्रह्मण्यम, जनसंपर्क अधिकारी संतोष कुमार तिवारी, आरआई शैलेन्द्र सिंह सहित वैधायिक संवर्ग के संकाय मौजूद रहे।

बिजलीघर मॉडल रोड को बना दिया ऑटो-ई रिक्शा स्टैंड

आगरा। तत्कालीन पुलिस आयुक्त जे रविन्दर गौड ने बिजलीघर चौराहे को मॉडल के रूप में विकसित किया मगर अब यह चौराहा ऑटो-ई रिक्शा और बस स्टैंड बनकर रह गया है। पांच रास्तों पर जाने के लिए राहगीरों से लेकर निजी वाहन चालकों को जदोजहद करनी पड़ती है। क्षेत्रीय लोगों का आरोप है कि पुलिस की लापरवाही से यहां वाहन बेतरतीब तरीके से खड़े होते हैं और लोगों को घंटों जाम का सामना करना पड़ता है।

बिजलीघर की तरफ से मंटोला की तरफ के रास्ते पर ऑटो की लंबी लाइन राह चलते लोगों को परेशान करती है। चालक सवारियों को बैठाने के लिए बीच सड़क पर ही ऑटो खड़ा कर देते हैं। लोग बुलाने पर नहीं आते हैं तो उन्हें हाथ पकड़कर बैठाने का प्रयास करते हैं। आलम यह है कि पुलिसवाले सामने खड़े रहने के बावजूद कुछ नहीं बोलते। यह हाल मंटोला तक है।

दो साल पहले पुलिस आयुक्त जे रविन्दर गौड ने बिजलीघर सहित 10 चौराहों को मॉडल बनाने के लिए चर्चान्त किया था। इसमें एक टीआई की इयूटी लगाई गई थी। यह देखा जाना था कि चौराहे पर अतिक्रमण और ऑटो स्टैंड पर कैसे रोक लगाई जा सकती है। स्मार्ट सिटी के कैमरों से चौराहे की व्यवस्था देखी जाती थी मगर कुछ

उत्तर प्रदेश

कपास की ओर बढ़ा किसान का रुझान, फिर बढ़ने लगा रकबा

अलीगढ़। खेतों में अब पारंपरिक धान-गेहूं की फसलों के साथ कपास की सफेदी भी नजर आने लगी है। पिछले साल कपास के अच्छे भाव ने किसानों का भरोसा लौटाया तो इस बार जिले में कपास का रकबा 3058 हेक्टेयर तक बढ़ गया।

विश्व स्तर पर सात अक्टूबर को कपास दिवस मनाया जाएगा। यह कपास के महत्व को पहचानने के लिए मनाया जाता है। जिले में पिछले साल 2420 हेक्टेयर में कपास



बोई गई थी, जो इस बार बढ़कर 5478 हेक्टेयर हो गई है। गभाना, चंडौस और बरीली क्षेत्र में किसानों ने पारंपरिक फसलों से हटकर कपास की खेती को तवज्जो दी है। उधर, सर्दी शुरू होने से पहले ही मंडी में अगैती कपास की आवक भी शुरू हो गई है। देसी कपास करीब 7000 रुपये और अमेरिकी कपास 6500 रुपये प्रति क्विंटल तक बिक रही है। अच्छी कीमत मिलने से किसानों के चेहरे खिले हैं। मंडी से कपास

स्थानीय मिलों में भेजी जाएगी, जहां इससे रूई तैयार होगी।

गभाना के गांव पैराई के किसान राहुल सिंह गुड़िया ने बताया कि पहले क्षेत्र में बड़े पैमाने पर कपास होती थी, लेकिन भाव गिरने पर किसानों ने दूसरी फसलों का रुख कर लिया। पिछले साल अच्छे दाम मिले तो उन्होंने इस बार करीब 15 हेक्टेयर में कपास बोई। अब शुरुआती आवक में ही बेहतर भाव मिलने से उम्मीद बढ़ी है।

मुश्किल में भारत-अमेरिका ट्रेड डील,

2000 करोड़ का निर्यात दांव पर, विशेषज्ञ बोले- अब नए देशों का रुख

कानपुर। अमेरिका-भारत मुक्त व्यापार समझौते पर असमंजस वाले वित्तमंत्री के बयान ने कानपुर के निर्यातकों में भी खलबली मचा दी है। शहर के निर्यातकों के लिए सबसे बड़े बाजार अमेरिका को होने वाले दो हजार करोड़ से ज्यादा का निर्यात दांव पर लगा है। निर्यातक पहले से ही टैरिफ, कच्चा माल की महंगाई, माल भाड़ा की बढ़ती कीमतों से जूझ रहे हैं। एक साल से अधिक समय से अमेरिकी टैरिफ की धमकियों से भी परेशान हैं।

अब भविष्य में भी जल्द समझौता न होने की अटकलों ने परेशानियां और बढ़ा दी हैं। अमेरिका के 22.50 प्रतिशत मौजूदा टैरिफ के कारण उत्पादों की लागत पहले ही बढ़ी है। अमेरिकी सीनेट ने तेल खरीद पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगाने की अनुमति अमेरिकी राष्ट्रपति को दे दी है। अमेरिका में शहर के चमड़ा उत्पादों की सबसे ज्यादा मांग होती रही है।

नए आर्डर भी नहीं मिल रहे हैं : साल 2024 में शहर से 1800 करोड़ का चमड़ा उत्पादों का निर्यात किया गया जो 2025 में 2300 करोड़ हो गया था। 2026 में ये 1700 करोड़ के करीब आ गया। वित्तीय वर्ष 2026-27 के पहले तिमाही के निर्यात आंकड़ों में 571 करोड़ की कमी दर्ज की गई है। अमेरिका-ईरान युद्ध के बाद होर्मुज जलडमरूमध्य के बंद होने से पानी के जहाजों से जाने वाले कंसाइनमेंट जाना बंद हो गए या लंबी दूरी तय करके जा रहे हैं। इससे निर्यातकों की उत्पाद लागत बढ़ गई है। नए आर्डर भी नहीं मिल रहे हैं।

2 16 हजार फीट से एचएपी का पहला लाइव जंप, आगरा की एडीआरडी ने रचा नया कीर्तिमान

आगरा। आगरा स्थित एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट (एडीआरडी) की ओर से डिजाइन और विकसित एडवॉंस्ड हार्ड-एल्टीट्यूड पैराशूट (एचएपी) का पहला लाइव जंप सफल रहा है। पूर्वी लद्दाख के न्योमा (मुधु) ड्रॉप जोन में 16 हजार फीट की ऊंचाई से पैराट्रूपर ने छलांग लगाई। परीक्षण में पैराशूट 15,500 फीट की ऊंचाई पर खुला और करीब 13,700 फीट की ऊंचाई पर स्थित न्योमा मुधु ड्रॉप जोन में सुरक्षित लैंडिंग हुई। एचएपी स्टैटिक लाइन पैराशूट प्रणाली है, जिससे बड़ी संख्या में पैराट्रूपर्स को एक साथ उतारा जा सकता है। विमान से जुड़ी स्टैटिक लाइन के जरिये पैराशूट स्वतः खुल जाता है। एचएपी की परिचालन ऊंचाई 18,000 फीट तक है। इसकी उतरने की दर अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए सुरक्षित रखी गई है। इतनी ऊंचाई पर स्टैटिक लाइन से छलांग में पैराशूट खुलने पर तेज झटका और उतरने की अधिक दर के कारण जोखिम रहता है। इसका निर्माण ऑर्डनंस पैराशूट फैक्टरी, कानपुर ने किया। रक्षा उत्पादन विभाग के गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय ने निरीक्षण और सैन्य विमानन योग्यता एवं प्रमाणन केंद्र, क्षेत्रीय सैन्य उड़न योग्यता केंद्र कानपुर ने प्रमाणन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम बताया। रक्षा सचिव, रक्षा अनुसंधान एवं विकास सचिव और डीआरडीओ अध्यक्ष राजेश कुमार सिंह ने टीम को बधाई दी।



→ व्यापार समझौते पर वित्तमंत्री के बयान से निर्यातक भी असमंजस में हैं। टैरिफ संबंधी विधेयक पास होने के बाद निर्यात आर्डर होल्डर पर हैं। इसके अलावा अमेरिका-ईरान युद्ध, रूस-यूक्रेन युद्ध से भी निर्यातकों की परेशानी बढ़ी है। अब वो नए-नए देशों के बाजारों की ओर रुख कर रहे हैं। **-आलोक श्रीवास्तव,** फियो, उत्तर प्रदेश, प्रमुख

→ जिस तरह के हालात बन रहे हैं, उनको देखते हुए निर्यातक अब अमेरिका पर निर्भरता कम करेंगे और कर भी रहे हैं। अमेरिका के बाद यूरोपीय यूनियन शहर के निर्यातकों के लिए सबसे बड़ा बाजार है। अब यहां पर तेजी से पैठ बनाई जा

रही है। इसके अलावा लंदन, कनाडा, रूस, बेलारूस, जापान के साथ कारोबारी रिश्ते बढ़ा रहे हैं। **-यादवेंद्र सचान,** क्षेत्रीय अध्यक्ष, चर्म निर्यात परिषद

→ निर्यातकों के सामने समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। हर प्रकार का केमिकल महंगा हो चुका है। माल भाड़ा अपने उच्चतम स्तर पर है। नए आर्डर मिल नहीं रहे हैं। अमेरिका के साथ कारोबारी रिश्ते बेहद नाजुक दौर में पहुंच गए हैं। होर्मुज बंद होने से समस्या और बढ़ गई है। क्रिसमस का 500 करोड़ का बाजार इस बार नहीं मिल पाया।

-असद इराकी, पूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष, चर्म निर्यात परिषद

स्क्रीन से मंच तक...जेन-जी में बढ़ा रामलीला का आकर्षण

अलीगढ़। समय बदला, तकनीक बदली और मनोरंजन के तौर-तरीके भी बदले, लेकिन रामलीला के प्रति युवाओं का आकर्षण आज भी कायम है। रामलीला देखने पहुंचे युवा न सिर्फ मंचन का आनंद लेते नजर नहीं आए, बल्कि पात्रों और प्रसंगों से जुड़ी कहानी भी सोशल मीडिया पर साझा करते दिखे।

युवाओं का कहना था कि पहले पौराणिक कथाओं से जुड़ी जानकारी जुटाने में काफी समय लगता था, लेकिन अब सोशल मीडिया के माध्यम से किसी भी पात्र या प्रसंग के बारे में जानकारी मिल जाती है। युवाओं के मुताबिक रामलीला के पात्रों और उनसे जुड़े रोचक प्रसंगों को जानना उन्हें पसंद है। इससे न केवल उनकी रचि बढ़ती है, बल्कि किसी चर्चा या मंच पर वे अपनी बात तथ्यों के साथ रखने में



भी सक्षम होते हैं।

बोले जेन जी दर्शक ...

→ रामलीला देखना मुझे बचपन से पसंद है। इस बार भी दोस्तों के साथ यहां आई हूं। मंचन के साथ रामायण के पात्रों और प्रसंगों के बारे में जानने की कोशिश करती हूं। किसी बात की जानकारी न हो तो मोबाइल पर तुरंत देख लेती हूं। **- दिव्या शर्मा,** दुबे के पड़वा **→** रामलीला में सिर्फ मनोरंजन नहीं, बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। अलग-अलग पात्रों की अपनी

कहानी और महत्व है। सोशल मीडिया पर इनके बारे में रोचक जानकारी मिल जाती है, इसलिए रामलीला देखने के बाद उससे जुड़ी चीजें पढ़ना अच्छ लगता है।

- परी, कोयला वाली गली **→** आजकल मोबाइल और सोशल मीडिया के दौर में भी रामलीला देखने का अपना अलग मजा है। मंच पर पात्रों को देखकर उनसे जुड़ी कहानी जानने की उत्सुकता होती है। कई बार ऐसी बातें पता चलती हैं, जो पहले

मालूम नहीं थीं। **- लक्ष्मी,** नौरागाबाद **→** रामलीला की कहानियां हमें अपनी संस्कृति और परंपरा से जोड़ती हैं। मुझे खासतौर पर अलग-अलग पात्रों के बारे में जानना अच्छ लगता है। अगर किसी प्रसंग को लेकर मन में सवाल आता है, तो मोबाइल से तुरंत उसकी जानकारी मिल जाती है। **- वैष्णवी,** धांबी वाली गली

बिजलीघर चौराहे से ही छीपीटोला की तरफ जा सकते हैं। यहां पर फोटो पुलिस चौकी भी है। इसके सामने ही ऑटो और ई-रिक्शा खड़े रहते हैं। इसके अलावा फलों की ठेलों से भी आसपास का रास्ता घिरा रहता है। इन पर कोई रोक-टोक नहीं है। चौराहे पर लगी ट्रैफिक लाइट भी खराब पड़ी हैं।

ट्रांसपोर्ट नगर में भी राह मुश्किल : अमित कुमार सिंह ने बताया कि ट्रांसपोर्ट नगर में कई वर्कशॉप के बाहर वाहन खड़े रहते हैं। इससे जाम लगता है। आसपास कॉलोनी हैं। इनमें रहने वाले लोगों को रास्ते से निकलने में परेशानी होती है। स्कूली वाहन भी फंस जाते हैं। दोपहर में किसी ट्रक के आने पर रास्ता नहीं मिलता है। इन्हें खड़े कराने के लिए कोई पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। पुलिस से शिकायत के बाद भी समाधान नहीं हो रहा है।

आप भी दे सकते हैं जानकारी : अगर उजाला ने ऑपरेशन ट्रैफिक अभियान शुरू किया है। इसके तहत शहर के प्रमुख चौराहों पर टीम रोजाना पड़ताल करेगी। बिगड़ी हुई यातायात व्यवस्था को सामने लाएगी। इसके लिए अमर उजाला रिपोर्टर के मोबाइल नंबर 7906877703 पर व्हाट्सएप कर जानकारी दे सकते हैं।

मतदाता सूची में नाम जुड़वाने व लोन की जानकारी लेने पहुंचे लोग

गोरखपुर। नगर निगम परिसर स्थित पुरी लक्ष्मीबाई पार्क में चल रहे सेवा सेतु शिविर में मंगलवार को लोग अपनी जरूरतों और समस्याओं का समाधान कराने पहुंचे। किसी ने व्यापार के लिए ऋण की प्रक्रिया समझी तो कोई मतदाता सूची में नाम जुड़वाने और नाम में हुई गलती ठीक कराने के लिए पहुंचा। विभिन्न विभागों के स्टॉल पर लोगों को योजनाओं की पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और सुविधाओं की जानकारी दी गई। दूसरे दिन करीब 250 लोगों ने विभिन्न योजनाओं और सेवाओं का लाभ लिया।

माया बाजार निवासी अरविंद गुप्ता व्यापार बढ़ाने के लिए ऋण की जानकारी लेने पहुंचे। उन्होंने बताया कि व्यापार बढ़ाने के लिए ऋण लेना चाहते हैं और शिविर में आवेदन की प्रक्रिया समझने आए हैं। आरके श्रीवास्तव ने भी ऋण लेने के लिए आवेदन और प्रक्रिया की जानकारी ली। वहीं प्रिंस कुमार गुप्ता मतदाता सूची में नाम में हुई गलती ठीक कराने पहुंचे। उन्होंने कहा कि शिविर के माध्यम से समस्या का समाधान हो जाए तो काफी सहूलियत होगी। विकास

नामांकन भरने की तारीख खत्म, कुल 188 ने भरा पर्चा; 23 अक्टूबर को होगी वोटिंग-निर्देश जारी

लखनऊ। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि प्रदेश के पांच मेरठ खंड स्नातक, आगरा खंड स्नातक, वाराणसी खंड स्नातक, लखनऊ खंड स्नातक व इलाहाबाद-झांसी खंड स्नातक और छह शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों मेरठ खंड शिक्षक, आगरा खंड शिक्षक, वाराणसी खंड शिक्षक, लखनऊ खंड शिक्षक, बरेली-मुगदाबाद खंड शिक्षक और गोरखपुर-फैजाबाद खंड शिक्षक में 23 अक्टूबर को मतदान कराया जाएगा। मतदान को निष्पक्ष व पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने और मतदाताओं की पहचान सुनिश्चित करने संबंधी विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।फर्जी मतदान को रोकने के लिए ऐसे सभी मतदाता जिन्हें फोटो पहचान पत्र जारी किए गए हैं, उन्हें मताधिकार का प्रयोग करने से पूर्व अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।उन्होंने स्पष्ट किया कि जो निर्वाचक किसी कारणवश अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं, उन्हें मतदान से वंचित नहीं किया जाएगा। ऐसे मतदाताओं की पहचान साबित करने के लिए वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों की मान्यता दी गई है।

ये मान्य दस्तावेज हैं : आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, राज्य व केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकायों या अन्य निजी औद्योगिक घरानों की ओर से अपने कर्मचारियों को जारी सेवा पहचान-पत्र, सांसदों, विधायकों व पार्षदों को जारी सरकारी पहचान-पत्र, संबंधित शिक्षक या स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक जिस शैक्षणिक संस्था में नियोजित हो, उस संस्था द्वारा जारी सेवा पहचान-पत्र, विश्वविद्यालय द्वारा जारी डिग्री/डिप्लोमा का मूल प्रमाण-पत्र, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता संबंधी मूल प्रमाण-पत्र, केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, द्वारा जारी यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड।

सांस्कृतिक प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने दिखाई प्रतिभा

कानपुर। इनिशिएटिव फॉर मोरल एंड कल्चरल ट्रेनिंग फाउंडेशन (आईएमसीटीएफ) एवं गुरुकुल संगीत विद्यापीठ के संयुक्त तत्वावधान में मंगलवार को सरस्वती ज्ञान मंदिर में सांस्कृतिक एवं रचनात्मक प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। कक्षा छह से 12 तक के विद्यार्थियों ने गायन, लोकगीत, चित्रकला और पोस्टर निर्माण में प्रतिभा दिखाई। सांस्कृतिक विधाओं में एकल गायन, सामूहिक देशभक्ति गीत और लोकगीत प्रतियोगिताएं हुईं। रचनात्मक विधाओं में चित्रकला व पोस्टर प्रतियोगिता आयोजित की गई। करीब 10 विद्यालयों के विद्यार्थियों ने प्रतिभाग किया। इनमें दुर्गावती दुर्गा प्रसाद बालिका इंटर कॉलेज, सेठ मोतीलाल खेड़िया विशालाक्ष, कैलाश सरस्वती विद्या मंदिर, बीएनएसडी शिक्षा निकेतन व सनतन धर्म एजुकेशन सेंटर समेत अन्य शामिल रहे। आयोजकों के अनुसार अगली प्रतियोगिताएं नौ अक्टूबर को यूनाइटेड पब्लिक स्कूल इंटर कॉलेज, 24 अक्टूबर को डीडी विद्या निकेतन चकरी और 27 अक्टूबर को रतन चंद खत्री इंटर कॉलेज में होंगी।

संक्षिप्तसमाचार

5-स्टार होटल की पार्किंग में नगालैंड की महिला से छेड़छाड़ मामले में एक्शन, तीन आरोपी गिरफ्तार

नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली पुलिस ने 4 अक्टूबर को चाणक्यपुरी इलाके के एक पांच सितारा होटल की पार्किंग में हुई कथित छेड़छाड़ और



हमले के मामले में तीन युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता नगालैंड की रहने वाली हैं। महिला की शिकायत के अनुसार, वह पार्किंग क्षेत्र में खड़ी थीं। तभी तीन युवक कार से आए और उनके साथ बदतमीजी की तथा उन्हें जबरदस्ती कार में बैधाने की कोशिश की। जब उनकी दोस्तों ने हस्तक्षेप कर उन्हें बचाने की कोशिश की, तो आरोपियों ने उन पर भी हमला किया। दिल्ली पुलिस ने बताया कि आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की जांच चल रही है।

दिल्ली की जहरीली हवा में वाहनों का बड़ा योगदान

नई दिल्ली। दिल्ली की जहरीली हवा में वाहनों की भूमिका कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा इस



बात से लगाया जा सकता है कि राजधानी में परिवहन क्षेत्र से पीएम 2.5 का करीब 39 प्रतिशत, पीएम 10 का 19 प्रतिशत और नाइट्रोजन आक्साइड (नाक्स) का 81 प्रतिशत उत्सर्जन होता है। ऐसे में वाहनों के ईंधन में बदलाव दिल्ली की वायु गुणवत्ता सुधारने की रणनीति का अहम हिस्सा हो सकता है। हालांकि, वाहनों के लिए केवल एक ही वैकल्पिक ईंधन को समाधान मानना उचित नहीं होगा। यह बात द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट (टैरी) के वाहनों के ईंधन के तुलनात्मक आकलन संबंधी अध्ययन में सामने आई है। अध्ययन ने दिल्ली को देश के उन प्रमुख शहरों में शामिल किया है, जहां अलग-अलग ईंधन और तकनीकों के लिए उपलब्ध ढांचे का तुलनात्मक आकलन किया गया। इसमें सामने आया कि सीएनजी बुनियादी ढांचे के मामले में दिल्ली सबसे मजबूत स्थिति में है। वहीं ईंधी ढांचे के लिहाज से भी दिल्ली और बेंगलुरु नौ आकलन किए गए स्थानों में अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति में हैं। लेकिन रिपोर्ट का निष्कर्ष दिल्ली की ईवी नीति के लिए खासा मायने रखता है। केवल चार्जिंग केंद्रों की संख्या बढ़ा देना पर्याप्त नहीं है। पेट्रोल-डीजल या सीएनजी की तुलना में ईवी को चार्ज होने में अधिक समय लगता है। इसलिए समान संख्या में चार्जिंग केंद्र होने के बावजूद उनकी वास्तविक सेवा क्षमता कम हो सकती है। अध्ययन में दोपहिया वाहनों के लिए ईवी को दीर्घकाल का सबसे मजबूत विकल्प बताया गया है। लिपहिया वाहनों में भी मौजूदा समय में सीएनजी मजबूत है, लेकिन धीरे-धीरे ईवी के आगे आने का अनुमान है। निजी कारों में बदलाव धीमा रहने की संभावना है और सीएनजी लंबे समय तक मजबूत पुरक विकल्प बनी रह सकती है। व्यावसायिक चार पहिया वाहनों में ईवी दीर्घकाल में पसंदीदा विकल्प बन सकता है, जबकि सीएनजी संक्रमणकाल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अध्ययन ने डीजल को पर्यावरणीय और आर्थिक प्रदर्शन के लिहाज से कमजोर पाया है। वहीं सीएनजी ने कई श्रेणियों में तकनीकी, पर्यावरणीय और आर्थिक प्रदर्शन के बीच बेहतर संतुलन दिखाया। ईवी को स्थानीय वायु प्रदूषण घटाने में फायदा है, लेकिन मौजूदा बिजली मिश्रण, बैटरी निर्माण और कच्चे खनिजों पर निर्भरता उसके समग्र पर्यावरणीय आकलन को प्रभावित करती है। दिल्ली के लिए अध्ययन का संदेश साफ है, वाहन प्रदूषण घटाने के लिए केवल ईवी पर निर्भर रहने के बजाय वाहन के प्रकार और इस्तेमाल के हिसाब से रणनीति बनानी होगी। शहर में पहले से मजबूत सीएनजी ढांचे का इस्तेमाल संक्रमण के दौरान किया जा सकता है।

पीओके से पहलगाम तक: संयुक्त राष्ट्र में भारत ने ओआईसी को घेरा

संयुक्त राष्ट्र एजेंसी। भारत ने जम्मू-कश्मीर और पाकिस्तान में आतंकी ढांचे के खिलाफ दिल्ली की कार्रवाई पर इस्लामिक सहयोग संगठन की टिप्पणियों को सिर से खारिज करते हुए कहा कि संगठन 'पीड़ित और गुनहगार के बीच फर्क करने में असमर्थ' नजर आता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की छठी समिति में भारत की ओर से लोकसभा सांसद बिप्लव कुमार देब ने कहा कि पाकिस्तान से होने वाले सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ अपने लोगों की रक्षा करना भारत का अधिकार है और आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों को इसके परिणाम भुगतने होंगे। परिचम त्रिपुरा से सांसद बिप्लव कुमार देब ने मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा की छठी समिति में 'अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद को खत्म करने के उपायों' पर भारत का राष्ट्रीय वक्तव्य दिया। 15 सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल संयुक्त राष्ट्र के परिचायत्मक दौरे के लिए यहां पहुंचा



मकोका लगाने के बाद भी दर्ज होते रहे मर्डर और किडनैपिंग के केस

दिल्ली पुलिस की जांच पर अदालत की सख्त टिप्पणी, कहा- 'कार्रवाई के नाम पर आईवांश'

नई दिल्ली, एजेंसी। संगठित अपराध के एक गंभीर मामले में दिल्ली की एक विशेष अदालत ने पुलिस की कार्यशैली और जांच रिपोर्ट पर कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने बाहरी-उत्तर जिला के पुलिस उपायुक्त द्वारा पेश की गई रिपोर्ट को पूरी तरह से 'लापरवाह और महज आंखों में धूल झांकने वाला' करार दिया है। विशेष न्यायाधीश गौरव राव ने कहा कि महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) जैसी सख्त धाराएं लागू होने के बावजूद मुख्य आरोपी सालों तक बेखोफ घूमते रहे और कई संगीन अपराधों को अंजाम देते रहे,

लेकिन पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकी।



अदालत के अनुसार, यह मामला सितंबर 2020 में दर्ज हुई एक खट्टक से जुड़ा है। उस दौरान आरोपी मुकेश उर्फ पुनीत और

प्रदीप उर्फ गुरी पर मकोका लगाया गया था। मुकेश उर्फ पुनीत :



मकोका दर्ज होने के वक्त उस पर हत्या और प्रयास समेत करीब 20 मामले दर्ज थे। कानून लागू होने के बाद भी 2021 से 2024 के

बीच उस पर हत्या, डकैती और अपहरण के 8 नए मुकदमे दर्ज हुए। इसके बावजूद उसे फरवरी 2026 में जाकर गिरफ्तार किया जा सका, जब केस नए अधिकारी को सौंपा गया।

प्रदीप उर्फ गुरी : प्रदीप पर भी मकोका के बाद लगातार संगीन अपराध करने के आरोप लगे। वह 2024 के दो नए मामलों में नामजद था, लेकिन उसे अप्रैल 2026 में गिरफ्तार किया गया।

तीन आरोपी अब भी फरार: विनोद, प्रदीप और विकास नाम के तीन अन्य आरोपी 6 साल बीत जाने के बाद भी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं।

पुलिस अधिकारियों ने सर्वोत्तम प्रयास किए

पिछली सुनवाई पर अदालत ने पुलिस से स्पष्टीकरण मांगा था कि आरोपी मकोका लगने के दौरान जमानत पर थे या हिरासत में और इतने सालों तक उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। हालांकि, डीसीपी द्वारा दायर रिपोर्ट में इन मुख्य सवालों पर पूरी तरह चुप्पी साध ली गई। इसके विपरीत, एडिशनल डीसीपी ने अपनी दलील में कहा कि 'पुलिस अधिकारियों ने अपनी तरफ से सर्वोत्तम प्रयास किए हैं।' इस पर अदालत ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि अधिकारियों की नजर में यही उनका सर्वश्रेष्ठ प्रयास है, तो कोर्ट के पास कहने को कुछ नहीं बचता। अदालत ने कहा कि अफसर मकोका जैसे कड़े कानून की भावना और जनता के प्रति अपनी जवाबदेही को लेकर पूरी तरह असंवेदनशील नजर आते हैं।

दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस स्थित कार्यालय में लगी आग, फर्नीचर जलकर खाक; कोई हताहत नहीं

नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली यूनिवर्सिटी (डीयू) के नॉर्थ कैंपस में स्थिति एक कार्यालय में देर रात अचानक आग लग गई। अधिकारियों के अनुसार, यह घटना मंगलवार रात करीब 11:53 बजे की है। आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और राहत कार्य शुरू किया। दमकल विभाग के अधिकारियों ने बताया कि आग कार्यालय कक्ष के भीतर लगी थी, जिसने वहां रखे सोफे, कुर्सियों और अन्य लकड़ी



के फर्नीचर को अपनी चपेट में ले लिया। आग फैलने के कारण कमरे में धुआं भर गया। सूचना मिलते ही दमकल कर्मियों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर राहत अभियान चलाया और जल्द ही आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया। राहत की बात यह रही कि घटना देर रात की थी जब दफ्तर बंद था, जिससे कोई भी व्यक्ति इसकी चपेट में नहीं आया और किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। हालांकि, कमरे में रखा फर्नीचर और कुछ दस्तावेज जलकर खाक हो गए हैं। आग लगने का प्राथमिक कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। शुरुआती तौर पर शॉर्ट सर्किट को वजह माना जा रहा है। पुलिस और दमकल विभाग की टीम घटना के सटीक कारणों की जांच कर रही है।

इस्राइल पर हमास के हमले के तीन साल, तब से जारी संघर्ष में अब कैसे हैं हालात

यरुशलम, एजेंसी। हमास के इस्राइल पर किए गए हमले को आज तीन साल पूरे हो गए हैं। उस दिन से शुरू हुआ हमास-इस्राइल संघर्ष आज भी जारी है। हालांकि, इस दौरान गाजा में बहुत कुछ बदल चुका है। ऐसे में आइए जानते हैं कि तीन साल पहले आखिर हुआ क्या था इसके बाद शुरू हुए हमास-इस्राइल संघर्ष में अब तक क्या-क्या हो चुका है इस संघर्ष में कितने लोग मारे गए कितना नुकसान हुआ मौजूदा स्थिति क्या है

7 अक्टूबर 2023 की सुबह यहूदी धर्म के प्रमुख त्योहार सिम्हत तोराह के दिन गाजा पट्टी से इस्राइल पर अचानक बड़ा हमला हुआ। हमास और दूसरे सशस्त्र समूहों ने एक साथ बड़ी संख्या में रॉकेट दागे। इसके बाद लड़कों ने गाजा और इस्राइल के बीच सुरक्षा अवरोध को कई जगहों से तोड़ा और जमीन, समुद्र और हवा के रास्ते दक्षिणी इस्राइल में दाखिल हुए। रॉयटर्स के मुताबिक, शुरुआती रॉकेट हमले में हमास ने करीब 3,000 रॉकेट दागने की बात कही थी, जबकि इस्राइली सेना ने

संख्या करीब 2,500 बताई थी। लड़कों मोटराइज्ड पैराग्लाइडर और नावों के जरिए भी इस्राइल में पहुंचे। हमलावरों ने गाजा सीमा के पास मौजूद कई कस्बों, किबुत्स और सैन्य



टिकानों को निशाना बनाया। नोवा म्यूजिक फेस्टिवल में मौजूद लोग भी हमले की चपेट में आए। इस्राइली अधिकारियों के अनुसार, हमले में 1,200 से ज्यादा लोग मारे गए और 251 लोगों को बंधक बनाकर गाजा ले जाया गया। हमले के कुछ ही घंटों बाद इस्राइल ने युद्ध की घोषणा कर दी। इसके बाद गाजा पर हवाई हमले शुरू हुए और अक्टूबर के शुरुआती दिनों में ही इस्राइल ने गाजा की नाकाबंदी कड़ी

कर दी। 13 अक्टूबर को इस्राइल ने उत्तरी गाजा और गाजा सिटी के निवासियों को दक्षिण की ओर जाने का आदेश दिया। इसके बाद बड़ी संख्या में लोग अपने घर छोड़कर दक्षिणी हिस्सों में चले गए। 27 अक्टूबर को इस्राइल ने गाजा में बड़े पैमाने पर जमीनी सैन्य अभियान शुरू किया। शुरुआत उत्तरी गाजा से हुई और बाद में अभियान दक्षिण की ओर बढ़ा।

इस्राइल का कहना था कि सैन्य कार्रवाई का लक्ष्य हमास की सैन्य क्षमता को खत्म करना और बंधक इस्त्रायली लोगों को वापस लाना है। इसी दौरान गाजा में लगातार हवाई हमले और जमीनी लड़ाई जारी रही।

कैसे बची कैप्टन स्मित की जान

‘लगातार बह रहा था खून, होंट भी पड़ गए थे नीले’

तेल अवीव, एजेंसी। तेल अवीव जा रही फ्लाईड्यूब्स की उड़ान में हुई चाकूबाजी से हर कोई हैरान है। 170 से ज्यादा यात्रियों की जान बचाने वाले पायलट स्मित मच्छर इसके असली हीरो रहे। दरअसर, उनके सह-पायलट ने अल हमाम ने अचानक उनपर चाकू से हमला कर दिया था। इसके बाद विमान काफी नीचे आ गया था। कुछ ही सेकंड में विमान क्रैश भी हो सकता था। लेकिन स्मित ने हार नहीं मानी। खून से लथपथ होने के बावजूद स्मित ने मुकाबला किया और मौका मिलते ही कॉकपिट का दरवाजा खोल दिया। इस दौरान चार यात्रियों ने तुरंत दौड़ लगाई। कुछ ने हमलावर को पकड़ा। एक ने विमान संभाला। उन्हीं चार में से एक दांतों के डॉक्टर भी थे। उन्होंने तुरंत स्मित को संभाला और उनकी जान बचाने पूरी ताकत झोंक दी। एक इंटरव्यू में जॉर्जियाई दंत चिकित्सक डॉ. शुता मुसाएव ने इस बारे में बात की। उन्होंने



बताया कि करीब 45 मिनट तक वो लगातार घावों पर दबाव बनाए रखे रहे। बर्फ की मदद से खून रोकने की कोशिश की। मुसाएव ने बताया कि कैप्टन के सिर और बाएं हाथ से बहुत ज्यादा खून निकल रहा था। उन्होंने पहले टी-शर्ट को घाव पर रखकर दबाव बनाया, लेकिन खून नहीं रुका। इसके बाद उन्होंने विमान के कर्मचारियों से बर्फ मांगी। कैप्टन के घाव बहुत गहरे थे, इसलिए कई आइस पैकेट इस्तेमाल करने पड़े। मुसाएव ने करीब 45 मिनट तक घाव पर दबाव बनाए रखा और बर्फ लगाते रहे। उनका कहना था कि जब भी वह खून देखने के लिए टी-शर्ट

हटाते थे, खून फिर तेज बहने लगता था। मुसाएव लगातार कैप्टन की हालत देखते रहे। वह उनसे बात करते रहे ताकि वह बेहोश न हों। उन्होंने कैप्टन से उनके बच्चों के बारे में पूछा और कहा कि वह जल्द अपने परिवार के पास लौटेंगे। कैप्टन ने अपना नाम और उम्र बताई। उन्होंने बताया कि वह भारत से हैं और दुबई में रहते हैं। वह दर्द में थे और मदद की गुहार लगा रहे थे। एक समय उनकी नब्ब बहुत कम हो गई। तब मुसाएव ने उनके पैर ऊपर किए, जिसके बाद नब्ब फिर लौट आई। जब कैप्टन के होंट नीले पड़ने लगे तो उन्होंने विमान कर्मचारियों से जल्द लैंडिंग कराने को कहा। कैप्टन दर्द की दवा मांग रहे थे। मुसाएव ने उन्हें थोड़ा-थोड़ा पानी दिया, लेकिन भारी खून बहने के कारण दवा देने से मना कर दिया। उन्हें डर था कि कैप्टन को हिलाने या दवा देने से दोबारा ज्यादा खून निकल सकता है।

वोटर लिस्ट में नाम बचाने दिल्ली आई बुशरा

एसआईआर नोटिस के जवाब में खर्च किए डेढ़ लाख

नई दिल्ली, एजेंसी। एसआइआर को लेकर मचे राजनीतिक घमासान के बीच एक ऐसा मामला सामने आया है, जो चिंता के साथ संवैधानिक अधिकार को सुरक्षित रखने की मिसाल देता है। पुरानी दिल्ली निवासी एक महिला ने को मतदाता सूची में अपना नाम सुरक्षित रखने के लिए करीब डेढ़ लाख रुपये खर्च कर कनाडा से 12 हजार किमी तक की हवाई यात्रा तय कर दिल्ली पहुंची है। मामला मटिया महल की बुशरा सुल्तान का है। उन्हें नोटिस का जवाब देने और निस्तारण के लिए पिछले माह कनाडा से दिल्ली आना पड़ा।

डेढ़ लाख की पलाइटी ली, अब वापस लौट गई बुशरा

वैक्कूर में बीमार बेटी के पास मौजूद बुशरा को नोटिस की प्रक्रिया पूरी करने के लिए 28 सितंबर की पलाइट पकड़ी, जिसका एक तरफ का हवाई किराया ही करीब डेढ़ लाख रुपये का था। दिल्ली आने के बाद उन्होंने प्रक्रिया पूरी की। उनका आरोप है कि उन्हें समय रहते बीएलओ द्वारा ऑनलाइन सुनवाई की सुविधा की जानकारी नहीं दी गई और बूथ पर आने के लिए मजबूर किया गया। इस कारण उनके परिवार को आर्थिक व मानसिक नुकसान झेलना पड़ा है।

वह मटियामहल विधानसभा के पार्ट नंबर पांच की मतदाता हैं। एसआइआर के दौरान उन्होंने एन्युमरेशन फार्म जमा की थी। उनका नाम ड्राफ्ट रोल में शामिल भी हो गया।

तोनहीं होता नुकसान...

इस दौरान 22 सितंबर को उन्हें नाम में त्रुटि का नोटिस मिला। तब उन्होंने बीएलओ से संपर्क किया। जिसने, उन्हें बताया कि फोटो अपलोड करने के लिए उनका मौके पर मौजूद रहना जरूरी है। तब उन्होंने परेशानी बीएलए- दो के जरिये अधिकारियों को भी दी, लेकिन कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं मिली। इसलिए उन्हें आना पड़ा। अगर, ऑनलाइन नोटिस प्रक्रिया निस्तारण की जानकारी दे दी होती तो न तो उनको आर्थिक नुकसान होता और न ही परेशानी। बुशरा के मामले की जानकारी नहीं है। जबकि, वह रोजाना बीएलओ के साथ बैठक करते हैं। अगर उन्हें समय रहते मामले की जानकारी दी जाती तो कोई दूसरी व्यवस्था की जा सकती थी।

बोला- पीड़ित और गुनहगार में फर्क करना सीखाए

ध्यान देना चाहिए। देब ने खास तौर पर रावलाकोट का जिक्र करते हुए कहा कि वहां लोगों की हत्याएं, हिंसा और बुनियादी अधिकारों से वंचित किए जाने की घटनाएं साफ दिखाई देती हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की जानबूझकर की गई अनदेखी सिर्फ कट्टरता और असहिष्णुता को दर्शाती है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पिछले कई महीनों से 12 विवादित शरणार्थी सीटों को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इन प्रदर्शनों के दौरान सुरक्षा बलों की कार्रवाई की गई है। हाल ही में हुए तथाकथित विधानसभा चुनावों में भी थांधली के आरोप सामने आए हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा की छठी समिति की ओर से सऊदी अरब ने बयान दिया। यह समिति मुख्य रूप से कानूनी मामलों से जुड़ी है। अपने बयान में 'दक्षिण-पूर्व एशिया में

सैन्य तनाव' और पाकिस्तान में 'कई स्थानों पर किए गए अनुचित हमलों' का जिक्र किया था। हालांकि, इस बयान में भारत का नाम सीधे तौर पर नहीं लिया गया था। भारत ने पिछले साल अप्रैल में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में मई में 'ऑपरेशन सिंदूर' शुरू किया था। इस अभियान के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर में मौजूद आतंकी ढांचे को निशाना बनाया गया था। 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले में 26 नागरिकों, जिनमें ज्यादातर पर्यटक थे, की मौत हुई थी। भारत ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमला उसकी संप्रभुता पर सोचा-समझा हमला था। देब ने कहा कि इस हमले की योजना और उसे अंजाम देने में ऐसे नेटवर्क शामिल थे, जिन्हें

भारत के पश्चिमी पड़ोसी से लगातार राज्य का संरक्षण, सुरक्षित टिकाने और आर्थिक एवं लॉजिस्टिक मदद मिलती रही है। हमले की जिम्मेदारी द रजिस्ट्रेंस फ्रंट ने ली थी, जिसे पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का प्रॉक्सी माना जाता है। देब ने संयुक्त राष्ट्र में कहा कि आतंकवाद के हर रूप और हर तरीके के खिलाफ लड़ाई जरूरी है। उन्होंने कहा कि सीमा पार आतंकवाद समेत आतंकवाद आज मानवता के सामने सबसे गंभीर खतरों में से एक है। इसका असर अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के साथ-साथ आर्थिक विकास, लोकतांत्रिक व्यवस्था और मानवाधिकारों पर भी पड़ता है। देब ने कहा कि आतंकवाद हर इंसान के सबसे बुनियादी अधिकार यानी जीवन के अधिकार पर हमला करता है।



संपादकीय

मौसम की दोहरी मार: यूरोप में सूखा से बड़ी चिंता

इस साल यूरोप में गर्मी और सूखे ने अनाज की पैदावार का अनुमान जितना घटाया है, उसका हिसाब अब अरबों यूरो में सामने आ रहा है. नई गणना के मुताबिक जून से सितंबर के बीच यूरोप की गेहूँ, मक्का और जौ जैसी अनाज फसलों के उत्पादन का अनुमान 16.7 मिलियन टन घटा है. मौजूदा कीमतों पर इसकी कीमत करीब 3.2 अरब यूरो बैठती है. एनजी एंड क्लाइमेट इंस्टिलिजेंस यूनिट यानी ईसीआईयू के मुताबिक पश्चिमी यूरोप ने इस साल गर्मी के मौसम में रिकॉर्ड गर्मी देखी. गर्मी ने गेहूँ में दाने भरने की प्रक्रिया और मक्के के परागण को प्रभावित किया. कई जगह मक्के की खेती का रकबा भी घटा. ब्रिटेन में जुलाई इंग्लैंड और वेल्स के लिए रिकॉर्ड पर सबसे सूखा रहा. वहां मई और जून की गर्मी के साथ मिलकर अनाज उत्पादन में करीब 3 मिलियन टन की कमी का

अनुमान है. यूरोप के इस आंकड़े की एक अहम बात यह है कि यह सीधे खेत से दर्ज हुआ अंतिम नुकसान नहीं है.यह उत्पादन के पूर्वानुमानों में आया बदलाव है, जिसे मौजूदा कीमतों से जोड़कर आर्थिक नुकसान का अनुमान लगाया गया है. ईसीआईयू ने यह भी बताया है कि रोमानिया, बुल्गारिया, पोलैंड और स्वीडन में उत्पादन के ऊपर की ओर संशोधन को अलग कर दिया जाए तो पश्चिमी और मध्य यूरोप में नुकसान का अनुमान 4.1 अरब यूरो तक पहुंचता है. भारत में 2026 के मौसम से जुड़ी फसल क्षति का ऐसा राष्ट्रीय आकलन उपलब्ध नहीं है, जिसमें मौसम से हुए अनाज के नुकसान को मिलियन टन और रुपए की कीमत में जोड़ा गया हो. लेकिन इस साल का मानसून खेती पर दबाव के कई संकेत जरूर छोड़ गया है.



भारत में जून से सितंबर के बीच दक्षिण-पश्चिम मानसून की बारिश लंबी अवधि के औसत से 12.6 प्रतिशत कम रही. 2026 का मानसून 2015 के बाद सबसे कमजोर रहा. दक्षिण भारत में बारिश लंबी अवधि के औसत की सिर्फ 76

राज्यों में लंबे सूखे दौर ने फसल की अंतिम पैदावार को लेकर चिंता बढ़ाई है. दक्षिण भारत के जलाशयों में 24 सितंबर को लाइव स्टोरेज क्षमता का करीब 50 प्रतिशत पानी था, जबकि पूरे देश का आंकड़ा 79 प्रतिशत था. इसका असर खरीफ की बची फसलों के साथ आने वाली रबी बुवाई पर भी पड़ सकता है. इसी बीच 2026-27 के लिए भारत का खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य 373.93 मिलियन टन रखा गया है. 2025-26 में दर्ज 376.56 मिलियन टन के मुकाबले यह कम है. सरकार ने चावल के लिए 123.15 मिलियन टन और मक्के के लिए 31.04 मिलियन टन का खरीफ लक्ष्य रखा है. ये लक्ष्य हैं, अंतिम उत्पादन के आंकड़े नहीं. यही वह जगह है जहां भारत और यूरोप की कहानी को एक जैसा मानने से बचना जरूरी है. यूरोप के मामले में 16.7 मिलियन टन की संख्या उत्पादन

पूर्वानुमानों में आई गिरावट का अनुमान है. भारत में फिलहाल हमारे पास कमजोर मानसून, कुछ फसलों के घटे रकबे, करीब 611,000 हेक्टेयर में प्रारंभिक नुकसान की रिपोर्ट और कम खाद्यान्न लक्ष्य जैसे अलग-अलग संकेतक हैं. इन्हें जोड़कर अभी मौसम से हुई कुल टन या रुपए की क्षति बताना संभव नहीं है. भारत के लिए तत्काल चिंता केवल देश में अनाज की उपलब्धता की नहीं है. 1 सितंबर 2026 को केंद्रीय पूल में करीब 39.05 मिलियन टन चावल और 48 मिलियन टन गेहूँ का स्टॉक था. दोनों ही निर्धारित बाहर मानक से ऊपर थे. इसका मतलब है कि कमजोर एक मौसम अपने आप राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा संकट में बदल जाए, ऐसा जरूरी नहीं है. लेकिन इससे किसानों की आवां, स्थानीय बाजार और कुछ फसलों की कीमतों पर पड़ने वाला दबाव खत्म नहीं होता.

पीएम नरेंद्र मोदी: सेवा, संकल्प और राष्ट्रनिर्माण के 25 वर्ष

देवेंद्र फडणवीस

राजनीति में अनेक नेता आते हैं, कुछ नेता चुनाव जीतते हैं, कुछ सरकारें चलाते हैं, लेकिन कुछ नेतृत्व ऐसे होते हैं, जो देश के विकास के बारे में सोचने के तरीके को ही बदल देते हैं. नरेंद्र मोदीजी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्षों का सफर ऐसे ही परिवर्तन की यात्रा है. 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले नरेंद्र मोदीजी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष 7 अक्टूबर 2026 को पूर्ण हो रहे हैं. यह 25 वर्षों का सफर केवल एक राजनीतिक नेता के लंबे कार्यकाल का आकलन नहीं है; बल्कि यह भारत के विकास की बदलती दिशा, जनभागीदारी के माध्यम से राष्ट्रनिर्माण और सामान्य नागरिक की आकांक्षाओं को केंद्र में रखने वाले नेतृत्व की यात्रा है. गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में प्रशासन का अनुभव प्राप्त करने के बाद 26 मई 2014 को उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाली. मई 2026 में उनके प्रधानमंत्री पद के 12 वर्ष पूरे हुए. आज भी उनके नेतृत्व में तेज गति से विकास हो रहा है. गुजरात से दिल्ली तक का यह सफर आज भारत के विकास की व्यापक संकल्पना से जुड़ गया है. इस यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा महाराष्ट्र है. उद्योग, व्यापार, कृषि, शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और सामाजिक परिवर्तन की समृद्ध परंपरा वाले महाराष्ट्र को राष्ट्रीय विकास के केंद्र में लाने में केंद्र सरकार के विभिन्न निर्णयों और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है. 2014 से 2026 तक का कालखंड महाराष्ट्र के बुनियादी ढांचे के इतिहास में एक महत्वपूर्ण चरण साबित हुआ है. गुजरात के वडनगर जैसे छोटे शहर और एक सामान्य परिवार से आगे बढ़े नरेंद्र मोदीजी के सार्वजनिक जीवन की शुरुआत सामाजिक संगठन के कार्य से हुई. 1974 के गुजरात छात्र आंदोलन में भागीदारी, आपातकाल के दौरान भूमिगत जनजागरण और भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक कार्य का लंबा अनुभव उनके सफर के महत्वपूर्ण पड़ाव रहे हैं. 7 अक्टूबर 2001 को उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. मुख्यमंत्री के रूप में उनकी पहली बड़ी परीक्षाओं में से एक था 2001 के भूकंप के बाद पुनर्वास और पुनर्निर्माण का कार्य. इस दौरान प्रशासन के कामकाज में लक्ष्य, आंकड़े, समयसीमा और वास्तविक परिणामों को महत्व देने वाली कार्यशैली विकसित हुई. कितने घर बनाए गए, कितने परिवारों का पुनर्वास हुआ, कौन-सा काम पूरा हुआ और कहाँ अड़चनें हैं - इसका आकलन करने की पद्धति आगे चलकर उनकी प्रशासनिक शैली की पहचान बनी. गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदीजी के कार्यकाल में ऊर्जा, पानी, कृषि, उद्योग, शिक्षा और प्रशासन के क्षेत्रों में विभिन्न पहल की गई. वाइब्रेट गुजरात समिट के माध्यम से वैश्विक निवेशकों को गुजरात की ओर आकर्षित किया गया. उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, 2001 में एक लाख करोड़ रुपए से कम रहने वाला गुजरात का निर्यात मोदीजी के मार्गदर्शन में चार लाख करोड़ रुपए तक पहुंचा. 2014 में प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी संभालने के बाद नरेंद्र मोदीजी ने भारत के विकास की दिशा को व्यापक राष्ट्रीय लक्ष्यों से जोड़ा. विकसित भारत 2047 केवल आर्थिक विकास का लक्ष्य नहीं है, बल्कि आत्मनिर्भरता, बुनियादी ढांचा, प्रौद्योगिकी, सामाजिक समावेश, महिला सशक्तिकरण और सांस्कृतिक विरासत का समन्वय करने वाला राष्ट्रनिर्माण का लक्ष्य है. इसी दृष्टिकोण से अनेक राष्ट्रीय पहलों को गति मिली. 25 करोड़ नागरिकों को गरीबी रेखा से बाहर निकालना हो, देशभर के गरीबों और महिलाओं को जनधन के माध्यम से बैंकिंग सेवाओं से जोड़ना हो, मुद्रा और स्टार्टअप के माध्यम से युवाओं के लिए व्यापक अवसर उपलब्ध कराना हो, या दुनिया को यूपीआई जैसा अनूठा डिजिटल माध्यम देना - ऐसी अनेक उपलब्धियां हैं. सभी के लिए आवास, शौचालय और हर घर में नल जैसी बुनियादी सुविधाओं के क्षेत्र में भी उन्होंने काम किया.

क्यों इतने अधिक लोकप्रिय हैं विदेश मंत्री जयशंकर?

हरीश गुप्ता

यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन सच है. नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से विदेश मंत्रालय को अन्य मंत्रालयों की तुलना में अधिक महत्व प्राप्त हो गया है. मोदी नियमित रूप से विभिन्न मंत्रालयों के मंत्रियों और सचिवों के साथ उच्चस्तरीय समीक्षा बैठकें करते हैं और उनसे उनके प्रदर्शन, लक्ष्यों और समयसीमाओं के बारे में गहन पूछताछ करते हैं.

जबकि विदेश मंत्रालय इन सामूहिक समीक्षा बैठकों से काफी हद तक बाहर ही रहा है. इसका यह अर्थ नहीं है कि विदेश नीति का महत्व कम हो गया है. बल्कि इसके विपरीत, यह प्रधानमंत्री की विदेश मामलों पर सीधे और बेहद करीबी नियंत्रण बनाए रखने की प्राथमिकता को दर्शाता है.

विदेश नीति का संचालन विदेश मंत्री एस. जयशंकर और विदेश सचिव विक्रम मिसरी सहित अनुभवी

राजनयिकों द्वारा प्रतिदिन किया जाता है. लेकिन मोदी स्वयं औपचारिक तंत्रों के साथ-साथ प्रत्यक्ष संवाद के माध्यम से भी इस पर कड़ी नजर रखते हैं. सरकार के कामकाज से परिचित लोगों का कहना है कि मोदी और जयशंकर लगातार संपर्क में रहते हैं और अक्सर तात्कालिक मुद्दों पर दिन में कई बार बात करते हैं. विदेश सचिव को भी नियमित रूप से इस पूरी प्रक्रिया में शामिल किया जाता है. बुनियादी ढांचे, संपर्क और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों के सामने आने पर विदेश मंत्रालय की जांच-पड़ताल और भी कड़ी हो जाती है. उदाहरण के लिए, हालांकि बंदरगाह एवं जहाजरानी मंत्रालय परिचालन पक्ष संभालता है, लेकिन ईरान के साथ बातचीत और रणनीतिक जुड़ाव में विदेश मंत्रालय की भूमिका अनिवार्य रूप से सामने आ जाती है. दूसरे, विदेश मंत्रालय मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (सीसीएस) का एक महत्वपूर्ण घटक है. यह समिति बड़े रणनीतिक, विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर निर्णय लेती है.

इसलिए, जयशंकर का महत्व विदेश मंत्री की पारंपरिक भूमिका से कहीं अधिक है. वे वस्तुतः 24×7 मंत्री हैं, जिनका एक पैर दिल्ली में और दूसरा लगातार विदेशी धरती पर रहता है. पूर्व राजनयिक जयशंकर दृढ़, स्पष्टवादी और बेबाक हैं. भले ही वे कूटनीतिक जगत से आए हों, लेकिन स्पष्ट बोलने की जरूरत पड़ने पर वे जरा भी संकोच नहीं करते. राष्ट्रीय राजधानी में कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की बैठक से ठीक पहले, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के बारे में एक विस्तृत लेकिन 'गोपनीय' दस्तावेज अचानक सामने आया. इसमें केरल कैडर के इस आईएएस अधिकारी के राज्य में कथित भ्रष्ट सौदों में

शामिल होने और किस तरह वह शीर्ष चुनाव आयुक्त के पद तक पहुंचे, इसका विवरण दिया गया था.

विडंबना यह है कि उस समय राज्य में शासन या तो कांग्रेस के हाथ में था या वाम दलों के. लेकिन कई लोगों को आश्चर्य हुआ जब राज्य के मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में ज्ञानेश कुमार के कार्यकाल से संबंधित एक नोट लेकर पहुंचे. सतीशन ने कुमार के सदिध कार्यों की एक लंबी सूची प्रस्तुत की.

उन्होंने 20 साल पहले एर्नकुलम जिले के जिला मजिस्ट्रेट रहते हुए उनकी गतिविधियों का भी विवरण दिया. कई लोगों ने हैरानी जताई और मन ही मन सोचने लगे कि राज्य में कांग्रेस सरकारों ने उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की. लेकिन ए. के. एंटनी का नाम कौन ले सकता था, जो कांग्रेस में केरल के निर्विवाद राजनीतिक सम्राट माने जाते थे?



ज्ञानेश कुमार को 2007 से 2012 के बीच नौसेना प्रणाली और रक्षा उत्पादन जैसे क्षेत्रों को संभालने के लिए संयुक्त सचिव के रूप में केंद्र में लाया गया था. एंटनी रक्षा मंत्री थे और कहा जाता है कि जब राज्य में उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था, तब ज्ञानेश कुमार को वे केंद्र में लाए थे.

अब केरल के गृह मंत्री रमेश चैनिथला ने एक सड़क परियोजना को लेकर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सतर्कता विभाग से जांच के आदेश दिए हैं. आरोप है कि इस परियोजना में राज्य को नुकसान हुआ था और 2006 में एक मलेशियाई ठेकेदार ने आत्महत्या कर ली थी. लेकिन सवाल यह है कि राज्य 20 साल बाद क्यों जागा? कांग्रेस को इसका जवाब देना होगा और खास तौर पर राहुल गांधी के राजनीतिक गुरु माने जाने वाले एंटनी को -जिनका बेटा अब भाजपा में है.

राजनेता भीड़ जुटा सकते हैं, चुनाव जीत सकते हैं और

काफी प्रभाव रखते हैं. लेकिन जब वे बैंक में पहुंचते हैं तो भारतीय रिजर्व बैंक उन्हें एक अलग नजरिये से देखता है - 'पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन' (पीईपी) यानी राजनीतिक रूप से प्रभावशाली व्यक्ति. आरबीआई का कहना है कि राजनीतिक प्रभावशाली व्यक्ति होना अपने आप में किसी व्यक्ति को वित्तीय रूप से सदिध नहीं बनाता.

लेकिन बैंक ऐसे लोगों को बिना जांच के आगे नहीं बढ़ा सकते. बैंकों को उनके धन और संपत्ति के खोत का पता लगाने के लिए उचित कदम उठाने होते हैं और खाते की लगातार, अतिरिक्त निगरानी करनी होती है. इसमें एक दिलचस्प पहलू भी है. यदि कोई सामान्य ग्राहक बाद में पीईपी बन जाता है तो बैंक यह दिखावा नहीं कर सकता कि कुछ बदला ही नहीं है. लेकिन आरबीआई ने स्पष्ट कर दिया है: पीईपी वर्गीकरण जोखिम मूल्यांकन का एक साधन है, संदेह का प्रतीक नहीं. कड़ी निगरानी अनिवार्य है,

लेकिन भेदभाव नहीं.

करीब 20 वर्षों बाद कांग्रेस फिर वही दांव खेल रही है - उत्तर प्रदेश इकाई की अध्यक्ष के रूप में एक महिला की नियुक्ति. इससे पहले रीता बहुगुणा जोशी के साथ यह प्रयोग बुरी तरह विफल रहा था. रीता बहुगुणा जोशी ने 2007 से 2012 तक उत्तर प्रदेश कांग्रेस की कमान संभाली और बाद में कुछ समय समाजवादी पार्टी में रहने के बाद भाजपा में शामिल हो गईं.

कांग्रेस ने इससे पहले शीला दीक्षित को भी कुछ समय के लिए ब्राह्मणों और महिलाओं को आकर्षित करने के उद्देश्य से आगे किया था. अब पार्टी उसी सामाजिक समीकरण को साधने के लिए आराधना मिश्रा 'मोना' पर दांव लगा रही है. हालांकि, उत्तर प्रदेश की राजनीति पर नजर रखने वालों

का कहना है कि इस कदम से समाजवादी पार्टी के साथ सीट-बंटवारे की बातचीत अपेक्षाकृत आसान हो सकती है.

जब तक अजय राय प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष थे, तब तक यह बातचीत मुश्किल दिखाई दे रही थी. राय जमीनी स्तर के नेता हैं और उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में वाराणसी सीट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कड़ी चुनौती दी थी. आराधना मिश्रा को इसलिए चुना गया है.

क्योंकि वह पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी की बेटी हैं और सपा के साथ गठबंधन को आसान बना सकती हैं. रीता बहुगुणा जोशी भी दिवंगत हेमवती नंदन बहुगुणा की बेटी थीं और शीला दीक्षित दिवांगत उमा शंकर दीक्षित की बहू थीं. दिलचस्प बात यह है कि आराधना ने पीसीसी अध्यक्ष नियुक्त होने से पहले 26 अगस्त को अपने पिता के साथ अखिलेश यादव से मुलाकात की थी.

दुनिया के बदलते सामरिक और आर्थिक सनीकरणों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीति लगातार भारत की वैश्विक पहुंच को नए आयाम दे रही है। इसी व्यापक कूटनीतिक रणनीति की एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में स्विट्जरलैंड के साथ संबंधों को नई ऊंचाई तक ले जाने की दिशा में आज एक अहम कदम सामने आया। स्विस राष्ट्रपति गाइ पार्मेलिन की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने प्रवास एवं गतिशीलता, युवा पेशेवरों, परिवहन प्रौद्योगिकी, वैज्ञानिक अनुसंधान तथा नवाचार और स्टार्टअप सहयोग से जुड़े पांच महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए।

नीरज कुमार दुबे

व्यापार और निवेश से आगे बढ़कर रक्षा उत्पादन, परमाणु ऊर्जा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, विज्ञान, उन्नत प्रौद्योगिकी और वैश्विक कूटनीति तक साझेदारी का विस्तार यह संकेत देता है कि भारत-स्विट्जरलैंड संबंध अब एक नए रणनीतिक चरण में प्रवेश कर रहे हैं और मोदी की सक्रिय कूटनीति ने यूरोप के इस महत्वपूर्ण देश के साथ भारत की साझेदारी को जिस तेजी से व्यापक बनाया है, उसने अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिक हलकों का ध्यान खींचा है।

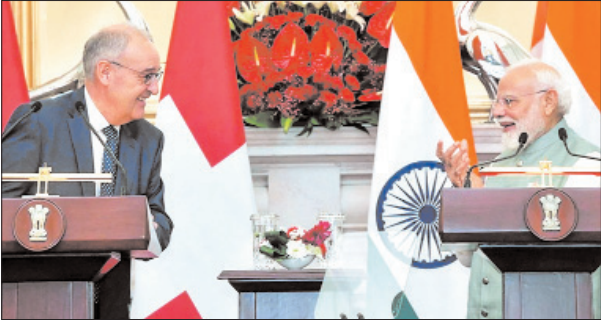
प्रधानमंत्री मोदी और गाइ पार्मेलिन की मुलाकात का सबसे बड़ा संदेश यह है कि भारत और स्विट्जरलैंड अब अपने रिश्ते को बहु-आयामी रणनीतिक साझेदारी में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। हैदराबाद हाउस में मोदी और पारमेलिन ने व्यापार एवं निवेश, एआई, नवाचार, रक्षा उत्पादन और सैन्य आदान-प्रदान, परमाणु ऊर्जा, विज्ञान-प्रौद्योगिकी तथा लोगों के बीच संपर्क सहित पूरे संबंधों की समीक्षा की। देखा जाये तो आर्थिक मोर्चे पर भारत-ईएफटीए व्यापार एवं आर्थिक साझेदारी समझौता इस रिश्ते की रीढ़ बनकर उभरा है। यह समझौता अक्टूबर 2025 में लागू हुआ था और स्विट्जरलैंड इसे भारतीय बाजार में स्विस कंपनियों की पहुंच और निवेश के लिए अधिक

निश्चितता देने वाला करार मानता है। स्विट्जरलैंड के अनुसार भारत एशिया में उसका दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और देश में 330 से अधिक स्विस कंपनियां सक्रिय हैं। द्विपक्षीय वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस समझौते के जरिए अगले 15 वर्षों में भारत में 100 अरब डॉलर के निवेश और 10 लाख प्रत्यक्ष रोजगार का लक्ष्य रखा गया है।

भारतीय कृषि उत्पादों, औषधियों, वस्त्रों और इंजीनियरिंग उत्पादों के लिए स्विस बाजार में अवसर बढ़ाने के साथ भारत जैव-प्रौद्योगिकी, जीवन विज्ञान, बैंकिंग, बीमा, खाद्य प्रसंस्करण और सतत विकास जैसे क्षेत्रों में स्विस निवेश आकर्षित करना चाहता है।

लेकिन इस साझेदारी का असली रणनीतिक विस्तार रक्षा और उन्नत प्रौद्योगिकी में दिखाई देता है। दोनों पक्षों ने सैन्य आदान-प्रदान और रक्षा उत्पादन में नए अवसर तलाशने तथा परमाणु ऊर्जा सहयोग को और गहरा करने पर सहमति जताई है। यह संकेत इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि स्विट्जरलैंड की उच्च तकनीकी औद्योगिक क्षमता और भारत

की बढ़ती रक्षा निर್ಮाण महत्वाकांक्षा मिलकर नए तकनीकी और औद्योगिक सहयोग के रास्ते खोल सकती हैं। साथ ही दोनों देशों के बीच बुनियादी ढांचे में भी सहयोग अब जमीन पर दिखाई दे रहा है। वाराणसी रोपवे, नोएडा के जेवर हवाई अड्डे और पर्वतीय क्षेत्रों में रेलवे तथा सुरंग परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए मोदी ने परिवहन, गतिशीलता और आधारभूत ढांचे पर नए



समझौते को आगे की साझेदारी का आधार बताया। समझौते में विद्युत वाहन, रोपवे, परिवहन अर्थव्यवस्था, सुरंग और टिकाऊ परिवहन प्रणालियों पर सहयोग शामिल है।

साथ ही विज्ञान और नवाचार इस रिश्ते की दूसरी बड़ी धुरी बन रहे हैं। भारतीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और स्विस राष्ट्रीय विज्ञान

प्रतिष्ठान के बीच समझौता दीर्घकालिक संयुक्त अनुसंधान का ढांचा तैयार करेगा। स्वास्थ्य, स्वच्छ ऊर्जा और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में नए संयुक्त शोध की शुरुआत भी प्रस्तावित है। ज्यूरिख विश्वविद्यालय के अनुप्रयुक्त विज्ञान संस्थान के साथ समझौते के जरिए शुरुआती चरण के भारतीय स्टार्टअप को प्रशिक्षण, तकनीकी हस्तांतरण, कार्यशालाओं और अंतरराष्ट्रीय नेटवर्किंग का अवसर मिलेगा।

मानव संसाधन के मोर्चे पर भी बड़ा बदलाव हुआ है। प्रवास एवं गतिशीलता साझेदारी के तहत पांच वर्ष तक वैध बहु-प्रवेश वीजा और प्रत्येक यात्रा में छह महीने तक ठहरने की सुविधा का प्रावधान है। छात्रों के लिए नवीकरणीय एक-वर्षीय अनुमति भी शामिल है। वहीं युवा पेशेवरों के आदान-प्रदान समझौते के तहत हर वर्ष दोनों देशों से 300-300 युवा पेशेवर भेजे जा सकेंगे, जिसे बढ़ाकर 500 तक किया जा सकता है। इसका उद्देश्य युवाओं को काम के साथ पेशेवर और भाषाई कौशल विकसित करने का अवसर देना है। यह समझौता प्रतिभा, तकनीक और पूंजी, तीनों को एक ही गलियारे में जोड़ता है। भारत को वैश्विक प्रतिभा और नवाचार नेटवर्क में प्रवेश मिलता है, जबकि स्विट्जरलैंड को भारत के विशाल प्रतिभा और

बाजार आधार से जुड़ने का अवसर मिलता है। इसके अलावा, दोनों देशों ने आगामी भारत-स्विस अनुसंधान प्रमुख कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र की भी घोषणा की है। साथ ही वैश्विक शांति, कूटनीति और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में सुधार की जरूरत पर दोनों पक्षों ने सहमति जताई है। यूक्रेन और पश्चिम एशिया जैसे संकटों पर भारत ने ह्रस्वार्थक शांति प्रयास के समर्थन की अपनी नीति दोहराई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इस रिश्ते का अगला मोर्चा है। भारत में 2026 के एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन के बाद स्विट्जरलैंड अगले चरण में जिनेवा एआई शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। दोनों देशों की कोशिश जिम्मेदार, समावेशी और मानव-केंद्रित कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए सहयोग बढ़ाने की है। नक्शेदेखें साफ है कि यह यात्रा केवल पांच समझौतों की कहानी नहीं है। इसके पीछे भारत की रणनीति यूरोप में व्यापार, निवेश, उन्नत तकनीक और विश्वसनीय आपूर्ति शृंखलाओं के नए केंद्रों से संबंध मजबूत करने की है, जबकि स्विट्जरलैंड भारत को अपने एशियाई आर्थिक और तकनीकी विस्तार के महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में देख रही है। 7 अक्टूबर का भारत-ईएफटीए 'प्रॉपेरेटी समिट' इस पूरी कवायद को निवेश और कारोबारी परियोजनाओं में बदलने की अगली परीक्षा होगा।

संक्षिप्त

समाचार

स्मृति मंधाना के लिए नई नहीं है कप्तानी

कुछ मौकों पर पहले भी संभाली है महिला टीम की कमान

नई दिल्ली। स्मृति मंधाना को भारतीय महिला क्रिकेट टीम का नया कप्तान नियुक्त किया गया है। मंधाना हरमनप्रीत कौर की जगह लेंगी और जिम्बाब्वे के खिलाफ सीमित ओवर सीरीज से उनके कार्यकाल का आगाज होगा।



कप्तानी हालांकि, नई नहीं है। वह इससे पहले भी कुछ मौकों पर भारतीय महिला टीम की कमान संभाल चुकी हैं। 2013 से भारतीय टीम का हिस्सा हैं मंधाना – साल 2013 से भारतीय टीम का हिस्सा रही मंधाना वनडे और टी20 अंतरराष्ट्रीय को मिलाकर कुल 22 मैचों में टीम की कमान संभाल चुकी हैं। मंधाना का रिकॉर्ड वनडे में कप्तान के तौर पर शानदार रहा है। उन्होंने कुल चार वनडे मुकाबलों में टीम की कप्तानी की है और सभी में जीत दिलाई है। वहीं, टी20 में भी मंधाना का रिकॉर्ड दमदार रहा है। उन्होंने कुल 18 मैचों में टीम की अगुआई की है, जिसमें से 11 मुकाबलों में टीम को जीत मिली है, जबकि सिर्फ छह मैचों में हार का सामना करना पड़ा है।

भारत के विजन को आईओसी से पहचान मिलने पर सम्मानित महसूस कर रहे हैं: पी. टी. उषा

नई दिल्ली। 12036 ओलंपिक और पैरालंपिक गेम्स की मेजबानी की भारत की उम्मीद एक कदम आगे बढ़ी है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन (आईओए) ने इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी की उस घोषणा का स्वागत किया है, जिसमें भविष्य के होस्ट चुनने की प्रक्रिया में हिस्सा लेने वाले शहरों और देशों के बारे में बताया गया है।



गुजरात के अहमदाबाद पर केंद्रित, भारत की बोली आईओसी के साथ सलाह-मशविरा करके बनाई जा रही है, जिसका विजन 'एक साथ उठना' थीम पर आधारित है। आईओए ने कहा कि यह विजन भारत की खेल संबंधी उम्मीदों को ओलंपिक मूवमेंट के दुनिया भर में अपनी पहुंच बढ़ाने के लक्ष्य के साथ जोड़ना चाहता है। प्रस्तावित गेम्स को सिर्फ एक बड़े खेल इवेंट के तौर पर नहीं, बल्कि भारत में खेलों में बड़े बदलाव के लिए एक कैटलिसट के तौर पर देखा जा रहा है।

टेनिस जगत को झटका, यानिक सिनर ने 2026 सीजन समाप्त करने की घोषणा की

नई दिल्ली। इटली के स्टार टेनिस खिलाड़ी यानिक सिनर ने मंगलवार को घुटने की घोट के कारण अपना 2026 सीजन समय से पहले समाप्त करने की घोषणा की। सिनर जुलाई से इस घोट से जूझ रहे थे। वर्ल्ड नंबर 1 यानिक सिनर विंबलडन जीतने के बाद से किसी टूर्नामेंट में नहीं खेले हैं और इसके बाद नॉर्थ अमेरिकन हार्ड-कोर्ट रिविंग और एशियन रिविंग में भी हिस्सा नहीं ले पाए।



सिनर ने सोशल मीडिया पर सीजन खत्म करने के फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि वह अपने घुटने का इलाज करवा रहे हैं। सिनर ने सोशल मीडिया पर कहा, 'मैंने और डॉक्टरों ने मिलकर तय किया है कि मुझे अपने घुटने का इलाज करवाना होगा, जिसका मतलब है कि 2026 सीजन आधिकारिक तौर पर खत्म हो गया है। पिछले कुछ वर्षों में, खासकर टयूरिन में सीजन के अंत में, मुझे बहुत अच्छी भावनाएं और अनुभव मिले, लेकिन यह साल अलग होने वाला है।'

कप्तान अख्यर का टी-20 में पहला शतक

नमन धीर का शानदार डेब्यू



भारत की लगातार 10वें टी20 में जीत

पहले टी-20 में वेस्टइंडीज को आठ विकेट से हराया



लखनऊ। भारत ने मंगलवार को वेस्टइंडीज को आठ विकेट से हराकर लगातार 10वीं टी20 अंतरराष्ट्रीय जीत दर्ज की। कप्तान श्रेयस अख्यर ने अपने करियर का पहला टी20 अंतरराष्ट्रीय शतक जड़ा, जबकि डेब्यू कर रहे ऑलराउंडर नमन धीर ने तीन विकेट लेकर भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई। पहले गेंदबाजी करते हुए भारत ने वेस्टइंडीज को 171 रन पर रोक दिया और फिर अख्यर (नाबाद 102) तथा ईशान किशन (नाबाद 37) की 137 रन की साझेदारी के दम पर 14.4 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया।

डेब्यू में ही नमन धीर ने लिए 3 विकेट

भारत के लिए नमन धीर ने गेंदबाजी में शानदार प्रदर्शन करते हुए 31 रन देकर तीन विकेट झटकें। कुलदीप यादव ने भी दो विकेट लिए। अक्षर पटेल और अर्शदीप सिंह को एक-एक सफलता मिली। वेस्टइंडीज की शुरुआत हालांकि तेज रही। कप्तान शाई होप ने दूसरे ओवर में मयंक यादव के खिलाफ लगातार चार चौके जड़ दिए।

अख्यर ने किशन के साथ

137 रन की साझेदारी की

अख्यर ने इसके बाद वेस्टइंडीज के गेंदबाजों की जमकर खबर ली। उन्होंने मैदान के चारों ओर शानदार शॉट लगाए और ईशान किशन के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए नाबाद 137 रन की साझेदारी की। अख्यर ने 42 गेंदों में अपना पहला टी20 अंतरराष्ट्रीय शतक पूरा किया। उन्होंने रॉस्टन चेज को गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से सीधा छक्का लगाकर शतक पूरा किया। उनकी पारी में शानदार चौके और छक्के शामिल रहे। ईशान किशन ने भी कप्तान का बखूबी साथ दिया और नाबाद 37 रन बनाए। अख्यर और ईशान की साझेदारी ने भारत के लिए लक्ष्य को बेहद आसान बना दिया।

श्रेयस ने कोहली का रिकॉर्ड तोड़ा, चेज करते हुए शतक लगाने वाले पहले भारतीय कप्तान

नई दिल्ली। भारतीय कप्तान श्रेयस अख्यर ने वेस्टइंडीज के खिलाफ मंगलवार को भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मैच में 102 रन की नाबाद पारी खेली। 43 गेंदों में अख्यर ने छह छक्कों और 10 चौके लगाए। इस पारी के साथ ही अख्यर ने रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी है। श्रेयस की इस दमदार पारी की मदद से भारत ने वेस्टइंडीज को आठ विकेट से हराया और सीरीज में 1-0 की बढ़त ले ली।

● सर्वोच्च रन बनाने वाले चौथे भारतीय – श्रेयस अख्यर बतौर कप्तान टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीयों की सूची में चौथे स्थान पर पहुंच गए हैं। शीर्ष तीनों पारियां रोहित शर्मा के नाम हैं, जिन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ नाबाद 121 रन, श्रीलंका के विरुद्ध 118 रन और वेस्टइंडीज के खिलाफ नाबाद 111 रन की पारियां खेली हैं। श्रेयस

अकेले ऐसे भारतीय कप्तान हैं, जिन्होंने रन चेज करते हुए शतक लगाया।

● ईशान के साथ रिकॉर्ड साझेदारी – टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में दूसरी पारी में बल्लेबाजी करते हुए किसी भारतीय कप्तान का पिछला सबसे बड़ा स्कोर 94* रन था, जो विराट कोहली ने 2019 में हैदराबाद में वेस्टइंडीज के खिलाफ बनाया था। अख्यर वेस्टइंडीज

के खिलाफ टी20 क्रिकेट में शतक लगाने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। उनसे पहले रोहित शर्मा (111*) और केएल राहुल (110*) यह कारनामा कर चुके थे। इस पारी के दौरान अख्यर ने ईशान किशन के साथ 137 रन की अटूट साझेदारी की, जो टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में रन चेज के दौरान भारत के लिए तीसरी सबसे बड़ी साझेदारी है।

सीनियर चयन समिति की बैठक में शामिल रहेंगे लक्ष्मण

नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के सचिव देवजीत सैकिया ने मंगलवार को कहा कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीओई) के प्रमुख सीनियर चयन समिति की सभी बैठकों में शामिल होंगे। वह गुवाहाटी में टी20 अंतरराष्ट्रीय और भारत ए टीम के चयन के लिए हुई बैठक में भी मौजूद थे। लक्ष्मण और अब पूर्व मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर के बीच संवाद की स्पष्ट कमी रही थी। माना जाता है कि चोटिल खिलाड़ियों के बारे में सीओई की ओर से समयसीमा की जानकारी नहीं मिलने के कारण कई बार अप्रिय स्थिति पैदा हुई। बेहतर संवाद के लिए होंगे शामिल

सैकिया ने कहा, अब से वीवीएस लक्ष्मण सीनियर चयन समिति की सभी बैठकों में शामिल होंगे ताकि चयनकर्ताओं और सीओई के बीच किसी तरह की संवादहीनता नहीं हो। मुंबई में हुई समीक्षा बैठक में यह फैसला लिया गया कि सीओई के क्रिकेट प्रमुख के तौर पर लक्ष्मण आगे से सभी बैठकों में शामिल होंगे। इसका उद्देश्य संवादहीनता को रोकना और चयनकर्ताओं को सही निर्णय लेने के लिए सटीक जानकारी उपलब्ध कराना है। बीसीसीआई ने मंगलवार को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक तस्वीर शेयर की, जिसमें लक्ष्मण को गुवाहाटी के एसीए स्टेडियम में हुई सीनियर पुरुष टीम की सिलेक्शन मीटिंग में देखा गया।

वया महिला चयन समिति के लिए लागू होगी व्यवस्था?

यह नियम सीनियर पुरुष टीम की चयन मीटिंग के लिए है, लेकिन अभी यह पता नहीं चला है कि सीनियर महिला टीम की सिलेक्शन मीटिंग के लिए भी यह व्यवस्था लागू की जाएगी या नहीं। पिछले कुछ महीनों में, चोट की वजह से कई महिला खिलाड़ियों की अहम टूर्नामेंट में उपलब्धता पर असर पड़ा है।



न्यूजीलैंड दौरे के लिए टी-20 टीम का ऐलान

चार साल बाद भुवनेश्वर की वापसी, श्रेयस कप्तान; पंत की फिटनेस पर रहेगी नजर

मुंबई। अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार की करीब चार साल बाद भारतीय टीम में वापसी हुई है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने मंगलवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली पांच मैचों की टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज के लिए टीम की घोषणा की। भुवनेश्वर को 16 सदस्यीय टी20 टीम में शामिल किया गया है। यह चयन समिति के पूर्व अध्यक्ष अजीत अगरकर के पद से हटने के बाद पहला बड़ा चयन है। प्रज्ञान ओझा को अंतरिम चयन समिति अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है।

चार साल बाद भुवनेश्वर की वापसी- भुवनेश्वर कुमार की वापसी इस टीम चयन की सबसे बड़ी खबर है। अनुभवी तेज गेंदबाज ने करीब चार साल बाद राष्ट्रीय टीम में जगह बनाई है।

22 अक्टूबर से शुरू होगी टी-20 सीरीज

भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज 22 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच खेली जाएगी। सीरीज का पहला मुकाबला क्राइस्टचर्च में होगा। इसके बाद तीसरा मुकाबला वेलिंगटन, जबकि चौथा और पांचवां मैच क्रमशः ऑकलैंड और हैमिल्टन में खेला जाएगा।

‘इतिहास आपको याद रखेगा’



नई दिल्ली। अजीत अगरकर का सीनियर पुरुष चयन समिति के प्रमुख के तौर पर कार्यकाल समाप्त हो गया है। अगरकर अब आगे इस पद पर नहीं रहेंगे। अगरकर का कार्यकाल यादगार रहने के साथ ही विवादों में भी घिर रहा। अब भारतीय टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने अगरकर को सराहा है। गंभीर का कहना है कि इतिहास अगरकर के प्रति ज्यादा उदार रहेगा।

चार अक्टूबर को खत्म हुआ कार्यकाल

अजीत अगरकर का मुख्य चयनकर्ता के रूप में कार्यकाल चार अक्टूबर को खत्म हो गया। इसके बाद गुवाहाटी में हुई टीम चयन बैठक में अगरकर मौजूद नहीं थे। रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने फिलहाल चयन समिति के सदस्य और पूर्व भारतीय स्पिनर प्रज्ञान ओझा को कार्यवाही की जिम्मेदारी संभालने को कहा है। ओझा अब अंतरिम चीफ सेलेक्टर के तौर पर काम कर रहे हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि प्रज्ञान ओझा स्थायी चीफ सेलेक्टर पद के लिए भी विकल्प बनकर उभरे हैं। चयन समिति में मौजूद सदस्यों में ओझा ने सबसे ज्यादा टेस्ट मैच खेले हैं।



अगरकर का कार्यकाल समाप्त होने पर बोले गंभीर, आपके साथ काम करना मेरे लिए सौभाग्य की बात?

गंभीर बोले-

अगरकर के साथ काम करना सौभाग्य की बात – अगरकर के साथ पिछले कुछ समय से गंभीर ने करीब से काम किया। अब जबकि अगरकर का कार्यकाल समाप्त हो गया है तो गंभीर ने सोशल मीडिया पर उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी हैं। गंभीर ने एक्स पर लिखा, प्रिय अजीत भाई, आपके साथ काम करना मेरे लिए बेहद सौभाग्य की बात रही। वे तीन पहले और टीम सबसे ऊपर। मैं कहना चाहूंगा कि इतिहास आपके प्रति ज्यादा उदार रहेगा। हर चीज के लिए शुक्रिया। आपको भविष्य के लिए मेरी दिल से शुभकामनाएं।

अगरकर के कार्यकाल में मिली यह बड़ी सफलताएं

अजीत अगरकर का भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता के तौर पर कार्यकाल कई बड़ी उपलब्धियों से भरा रहा। हालांकि, इसी दौरान विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविचंद्रन अश्विन जैसे दिग्गजों के अंतरराष्ट्रीय करियर में भी बड़े बदलाव हुए। अगरकर के कार्यकाल को सिर्फ विवादों के नजरिए से नहीं देखा जा सकता। उनके चयन पैनल के दौरान भारत ने तीन आईसीसी खिताब जीते। इनमें 2024 और 2026 के टी20 विश्व कप तथा 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी शामिल हैं। इसके अलावा भारत 2023 वनडे विश्व कप के फाइनल तक पहुंचा था। यानी अगरकर के नेतृत्व वाली चयन समिति के चुने स्वर्णों ने पिछले तीन वर्षों में चार आईसीसी सफेद गेंद टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बनाई और तीन खिताब जीते। अगरकर जुलाई 2023 में मुख्य चयनकर्ता बने थे।